खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) / अंक-33

मंगलवार 17 जनवरी, 2023 / 27 पौष, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) में अंक 32 से अंक 35 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-3 (भाग-4) मंगलवार, 17 जनवरी, 2023/27 पौष, 1944 (शक) अंक-33

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	4-45
3.	सदन में अव्यवस्था	46-50
4.	ध्यानाकर्षण (नियम-54) अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो रहे अवरोधों और दखलंदाजी के संबध में	51-90
5.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	91
6.	दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 का पुर:स्थापन	92
7.	ध्यानाकर्षण (नियम-54) झुग्गियां तोड़े जाने के नोटिस के संबंध में	93-132

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) मंगलवार, 17 जनवरी, 2023/27 पौष, 1944(शक) अंक-33

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.09 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
3 श्री अजय दत्त
4 सुश्री आतिशी
5 श्री अब्दुल रहमान
6 श्रीमती बंदना कुमारी
7 सुश्री भावना गौड
8 श्री बी. एस. जून
9 श्री धर्मपाल लाकड़ा
10 श्री दिनेश मोहनिया
11 श्री गिरीश सोनी
12 श्री गुलाब सिंह
13 श्री हाजी युनूस
14 श्री जय भगवान
15 श्री करतार सिंह तंवर
16 श्री कुलदीप कुमार
17 श्री महेंद्र गोयल
18 श्री मदन लाल

19 श्री नरेश बाल्यान
20 श्री नरेश यादव
21 श्री पवन शर्मा
22 श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
23 श्री प्रवीण कुमार
24 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
25 श्री ऋतुराज गोविंद
26 श्री रघुविंदर शौकीन
27 श्री राजेश गुप्ता
28 श्री राजेन्द्र पाल गौतम
29 श्रीमती राजकुमारी ढ़िल्लो
30 श्री राजेश ऋषि
31 श्री रोहित कुमार
32 श्री शरद कुमार चौहान
33 श्री सोमदत्त
34 श्री शिवचरण गोयल
35 श्री सौरभ भारद्वाज
36 श्री सहीराम
37 श्री एस के बग्गा
38 श्री सुरेंद्र कुमार
39 श्री विनय मिश्रा
40 श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
41 श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
42 श्री अभय वर्मा
43 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
44 श्री अजय कुमार महावर
45 श्री जितेन्द्र महाजन
46 श्री महेन्द्र यादव
47 श्री मोहन सिंह बिष्ट
48 श्री ओमप्रकाश शर्मा
49 श्री प्रलाद सिंह साहनी
50 श्री सोमनाथ भारती
51 श्री विजेंन्द्र गुप्ता
52 श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) मंगलवार, 17 जनवरी, 2023/27 पौष, 1944(शक) अंक-33

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.09 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः राष्ट्रीय गीत के लिये अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, प्लीज़। करने दीजिये, अब खड़े हो गये करने दीजिये। काली पगड़ी पहनकर आये हैं राष्ट्रगीत से धुल जायेगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः करिये शुरू करिये। भई नो कमेंट्स प्लीज़।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब पीली पगड़ी से काली पगड़ी पर आ गये हैं जरा करो ना भई, क्या हुआ।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (नेता प्रतिपक्ष): आपको हम सब लोग, आपको हम सब लोग जो है ना एडवांस में जन्मदिन की बधाई दे रहे थे।

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्

विशेष उल्लेख (नियम-280)

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का इस सत्र में दूसरे दिन हार्दिक स्वागत है, विशेष उल्लेख मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम में बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिम्म आज कवर हो जायें तो इसलिये जो भी लिमिट है उस लिमिट में बोलेंगे श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद सर, अपोरचूनिटी देने के लिये। सर, कुछ एक साल पहले पंजाब में एक पिक्चर आई थी "उड़ता पंजाब" वो इस बात पर थी कि पूरे पंजाब को जो है ना ड्रग एब्युज़ ने कंट्रोल कर लिया था आज वैसे ही हालात दिल्ली में होते जा रहे हैं चाहें कोई झुग्गी क्लस्टर हो, चाहें अनॉथराइज़ कॉलोनी हो, गांव हो इवन स्कूल्स में भी ड्रग्स जो है इतनी प्रिवलेंट हैं कि मतलब आप कह नहीं सकते अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जनरेशन कैसे खराब होती जा रही है और उसके लिये सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंसी जिम्मेवार है और वो है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई स्टैप्स नहीं लिया है जिससे ये ड्रग एब्युज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। drugs psychotropic substances बहुत इज़िली अवेलेवल हैं सब जगह और पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है सभी आपने, मैं आपको सर बताऊँ मेरे एरिया में 03.10.2022 को मैंने डीसीपी को लैटर लिखा कि ड्रग्स का प्रिविलेंट होना बहुत कॉमन हो गया हर जगह ड्रग्स अवेलेवल है तो पुलिस को कुछ

ना कोई कार्यवाही करनी चाहिये उस लैटर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई cognizance नहीं लिया गया सर और 22.11.2022 को एक महीने बाद चार मर्डर हुये एक घर में मेरे एरिया में, लड़के ने अपनी दादी, अपने माँ–बाप और बहन को वो ड्रग एडिक्ट था उसने मार दिया और हमने ओपन्ली लोगों की स्टेटमेंट्स के साथ लोकेशन दी थी की यहां ड्रग्स बिक रही है उसके बाद सर मैंने दोबारा से तीन दिन बाद एल.जी. साहब को चिट्ठी लिखी कमिश्नर ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और ड्रग्स के जो हैं हालात बहुत दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ड्रग्स ऐसे ही बिक रही है किसी की कोई रिस्पोन्सिब्लेटी, एकांउटेब्लेटी फिक्स नहीं की गई इवन एक बीट कॉन्सटेबल को भी जो है ट्रांस्फर नहीं किया गया हांलाकि चार मर्डर हुये टोटल फैमिली में पांच आदमी थे चार का मर्डर हो गया एक जेल चला गया तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई लेकिन पुलिस के कान पर आज तक जूं नहीं रेंगी तो मेरा सर क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इसमें पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये पूछा जाये कि भई जब पूरी सोसाएटी, पूरी जनरेशन बरबाद हो रही है तो पुलिस का इस मामले में क्या कर रही है क्योंकि आज तक किसी ये मेरा सिर्फ मेरी विधानसभा का चक्कर नहीं है ये पूरी दिल्ली में जितने भी हमारे विधायक बैठे हैं चाहें ये काली पगड़ी वाले बैठे हों इनसे भी पूछेंगे कि इनके एरियाज़ में भी ड्रग्स जो हैं इज़िली अवेलेवल हैं। बिजवासन का एक गर्वमेंट स्कूल है वहां प्रिंसीपल ने लड़के के बैग से ड्रग्स बरामद किया औरजो ड्रग्स पैडलर है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जो स्टूडेंस के खिलाफ एक्शन लिया वो माइनर है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती तो जितना

बुरा हाल आज स्कूलों में हो रहा है कॉलनिज़् में हो रहा है 7.00 बजे के बाद कोई रेस्पेक्टेबल आदमी किसी पार्क के नहीं जा सकता सारे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं तो मेरा एक अनुरोध है कि इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है तलब करके और उनसे जवाब मांगा जाये कि ड्रग्स के मामले में जनरेशन को सेव करने के लिये वो क्या कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः इसको केवल इनके क्षेत्र का मुद्दा मानकर हीना रखा जाये इस पर विस्तार से चर्चा करवाई जाये क्योंकि पूरे दिल्ली के बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, स्कूल के अंदर लोग फूल सुंघते हैं, चरस, गांजा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं डायरेक्ट एल.जी. तक से मिल चुका हूं पर्सनली उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं है तो इस तरीके से दिल्ली के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है तो नशे के आदी होते जा रहे हैं और ये मुद्दा कोई केवल एक विधानसभा का नहीं है पूरे दिल्ली के युवाओं के भविष्य का है इस पर विस्तार से कम से कम चर्चा करवाई जाये।

श्री बी.एस. जूनः तो सर ये लोग भी एग्री करेंगे।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ये मुद्दा केवल एक विधानसभा का नहीं है कि हमारे एक सदस्य माननीय सदस्य ने रख दी ये मेरी पूरी विधानसभा में, मैं डीसीपी से मिल चुका हूं मैं, मैं कमिश्नर को लिख चुका हूं मैं डायरेक्ट एल.जी. साहब जो पीछे थे उनसे पर्सनली मिलकर आया हूं और मैंने सारे मुद्दों को उठाया हैऔर आपकी मेरी विधानसभा का कोई नहीं है आपको भी मालूम होगा, उसके

बावजूद नशे को रोकने पर कोई गंभीरता से कार्यवाही नही हुई है मुझे लगता है इस पर चर्चा करनी चाहिये।

माननीय अध्यक्षः राजेन्द्र जी, इस पर मेरा ये कहना है गंभीर मुद्दा है वास्तविकता में इसको किसी नियम में चर्चा के लिये डालिये।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ठीक है साहब।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री अनिल वाजपेयी जी। माइक चालू करिये पीछे वाला।

श्री अनिल वाजपेयीः माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे नियम-280 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एसडीएम, गांधी नगर के कार्यालय को नन्द नगरी में स्थानांतरण करने की ओर दिलाना चाहता हूं आज से लगभग 10-11 साल पहले एसडीएम कार्यालय को नन्द नगरी भेज दिया गया था आज गांधी नगर विधानसभा के लोगों को आय प्रमाण-पत्र, मकान की registry, शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये कम से कम 10 किलोमीटर दूर नन्द नगरी जाना पड़ता है अध्यक्ष जी गांधी नगर से कोई सीधी ट्रांसपोर्ट सेवा नन्द नगरी जाने के लिये नहीं है जिससे पूरी विधानसभा के लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि एसडीएम इलैक्शन गांधी नगर है विधायक निधि से डूडा द्वारा इसका काम पूरा गांधी नगर में ही शास्त्री भारत नगर से किया गया है मैं कई बार आपके सम्मुख इस समस्या को उठा चुका हूं आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस कार्यालय को नन्द नगरी से वापिस पुश्ता रोड़ एसडीएम कार्यालय में वापिस लिया जाये जिससे गांधी नगर

क्षेत्र की जनता को परेशानी ना करना पड़े यदि एक माह के अंदर मैं कई बार विधानसभा में ये प्रश्न उठा चुका हूं माननीय अध्यक्ष जी अगर एक माह के अंदर ये वापिस नहीं लाया गया तो मैं गांधी नगर की जनता के साथ मैं धरने पर विवश हो जाऊँगा। हमारे बीच में बग्गा जी जो हमारी बगल वाली कॉन्सिटिट्वेन्सी से आते हैं माननीय ओमप्रकाश जी हैं जो समस्या मेरी है वो समस्या माननीय ओमप्रकाश जी की भी है और वो समस्या बग्गा जी की भी है तीनों, तीनों लोगों की समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी मैं व्यक्तिगत भी आपसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं और ये गांधी नगर की लोगों की जेन्युअन परेशानी है इसको प्लीज़ कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकाला जाये या डिविज़नल कमिश्नर को बुलाकर इसको सर कराया जाये। मैंने कल माननीय मंत्री कैलाश गहलौत जी से भी प्रार्थना की थी सर इसको मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं और तीन विधानसभा इससे इफैक्ट हो रही हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी, अनुपस्थित अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 280 में चर्चा पर समय देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, लोकपाल के नाम पर चुनकर आई हुई ये सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार, पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। लगातार दिल्ली सरकार के अनेक मंत्री उनके विभाग के भ्रष्टाचार के मामले जनता के सामने आ रहे हैं। चाहें दिल्ली परिवहन के निगम में बसों की खरीद का घोटाले का मामला हो, चाहें दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 60 हज़ार करोड़ का घोटाले का मामला हो, चाहें जिसका ऑडिट पिछले छः सालों से नहीं हुआ है सरकार में नई आबकारी नीति के

घोटाले के कारण भी काफी चर्चा रही। दिल्ली की जनता में भाजपा के लगातार विरोध के कारण विवश होकर सरकार को नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लास रूम के निर्माण में भी।

माननीय अध्यक्षः बोलने दो, जनता सब समझती है।

श्री अजय महावरः भारी घोटाला हुआ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें एक मंत्री पिछले सात महीने से जेल में बंद है लगातार माननीय न्यायालय द्वारा जमानत याचिकायें खारिज की जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबुझकर भ्रष्ट मंत्री को बचाने में लगे हुये हैं और जानबूझकर, जानबूझकर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों प्रार्थना है बैठिये।

श्री अजय महावरः उनको सुविधायें दी जा रही हैं भ्रष्ट मंत्री को रेपिस्ट उनकी सेवा कर रहे हैं उनको उनको कैबिनेट का तमगा दिया जा रहा है कैबिनेट में सुशोभित करके रखा जा रहा है ये घोर अन्याय है दिल्ली की जनता के साथ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई ये कट्टर बेईमान पार्टी है, ईमानदारी के नाम पर आई हुई ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान हो चुकी है और इसलिये।

माननीय अध्यक्षः बैठिये प्लीज़ बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये हो गया उन्होंने पूरा पढ़ लिया, पूरा हो गया उनका पूरा हो गया।

...व्यवधान...

श्री अजय महावरः इसीलिये, इसीलिये हम, मेरा ये कहना है।

...व्यवधान...

श्री अजय महावरः मुझे अपनी बात पूरी।

माननीय अध्यक्षः बैठिये श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, विजेन्द्र गुप्ता जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी, हो गया पूरा हो गया उनका, पूरा हो गया एक-एक वाक्य पूरा हो गया, जो इन्होंने लिखकर दिया वो पूरा हो गया पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं रिकार्ड निकलवा दें, रिकार्ड निकलवा दूं पूरा एक-एक अक्षर पढ़ चुके हैं, एक-एक अक्षर पढ़ चुके हैं अब मैं समय नहीं दे रहा हूं, बैठिये वो एक-एक अक्षर पढ़ चुके हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं।

माननीय अध्यक्षः एक-एक अक्षर वो पूरा पढ़ चुके हैं मैं सुन रहा हूं मैं निकलवाकर दिखा दूंगा आपको, जो इन्होंने बोला है पूरा निकलवाकर दिखा दूंगा आपको, ऑफिस में आ जायेगा निकलवाकर दिखादूंगा ।

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (नेता प्रतिपक्ष): डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दिया।

माननीय अध्यक्षः पूरा पढ़ा है उन्होंने एक-एक अक्षर पूरा पढ़ा है।

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (नेता प्रतिपक्ष): डिस्टर्ब किया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये आप, विजेन्द्र जी चालू करिये, विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी आप बोल रहे हैं नहीं, श्रीमान विजेन्द्र जी, श्रीमान विजेन्द्र गुप्ता जी।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः शांत तो कराईये, सदन को शांत तो कराईये तभी तो मैं बोलूंगा कैसे बोलूंगा मैं बताओ।

माननीय अध्यक्षः वो शांत बैठे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बोल रहे हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं बोलना चाहता हूं, मगर।

माननीय अध्यक्षः तो बोलिये ना जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः तो जब वो अब बैठेंगे तभी तो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये तो पूरा पढ़ चुके हैं वो।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब शांत तो कराईये ना सर इनको।

माननीय अध्यक्षः किसको।

श्री विजेंद्र गुप्ताः सदन को।

माननीय अध्यक्षः सदन शांत है। आप बोलना नहीं चाह रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिये आप बोलिये, नहीं अब पूरा हो चुका है अब मैं अजय महावर जी कुछ नहीं बोलूंगा अब पूरा कर चुके हैं एक-एक अक्षर पूरा कर चुके हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये, बैठ जाईये, बैठ जाईये अब डिस्टर्ब कौन कर रहा है ऋतुराज जी ऋतुराज जी आप चालू करिये छोड़िये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठ जाईये।

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः आप बोलना नहीं चाह रहे मैं क्या करूं, छः बार नाम बोला मैंने बोलिये आप बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, बोलिये, बैठिये।

श्री ऋतुराज गोविंदः ये मेरी विधानसभा का मुद्दा है।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी बैठिये।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः देख रहे हैं आप, क्या बद्तमीज आदमी है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब क्या हो रहा है ये, अब क्या हो रहा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं रोक रहा हूं, आप दो मिनट, ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः ये क्या तरीका है।

माननीय अध्यक्षः जो आपने लिखकर दिया है कृपया उसी को पढ़िये प्लीज़, बोलिये ऋतुराज जी इसके बाद दे रहा हूं आपको नम्बर विजेन्द्र जी विजेन्द्र जी ऋतुराज जी के बाद आपको दे रहा हूं।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, 280 में मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया जोकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरे दिल्ली में एकमात्र कॉन्सिटिट्वेन्सी है जो कि 99 परसेंट अनॉथराइज़ कॉलोनिज़ है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आर्शीवाद से आज की तारीख में ड्रेनीज़ और सिवरेज़ पर काम हो रहा

है लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसका ध्यान में पूरे सदन का दिलाना चाहता हूं कि पूरे दिल्ली के अंदर में हो सकता है कि वॉटर टैबल बहुत नीचे चला गया हो लेकिन किराड़ी कॉन्सिटिट्वेन्सी का जो पूरा का पूरा ज्योगरफिकल एरिया है उसके अंदर में वॉटर टैबल लगभग एक से डेढ़ फुट पर आ चुका है जिसके चलते चाहें हमें अस्पताल बनाना हो चाहें हमें स्कूल बनाना हो raft formation से आज कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं pile formation का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आप यकीन नहीं करेंगे 10-10 नये स्कूल बनाने हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना लेट इसलिये चल रहा है क्योंकि pile formation का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जनता जनार्दन के लिये जो अस्पताल बनाना है उसका दस प्रतिशत भी काम इसलिये नहीं हो पाया है क्योंकि pile formation का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो आठ लाख की आबादी रहती है वो इतने बड़े डर के साये में है कब पता नहीं क्या घटना घट जाये क्योंकि वॉटर टैबल इतना ऊपर आ चुका है। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं जब तक हमारे इलाके के अंदर में डिवॉटरिंग का प्रोसेस शुरू ना हो जाये जब तक दिल्ली जल बोर्ड या तो पानी निकालकर के दूसरी जगह सप्लाई करे या फिर जो पीडब्ल्यूडी वगैराह डिपार्टमेंट है जो नॉन ड्रिंकिंग वॉटर के लिये जो पानी इस्तेमाल करती है उसके लिये डीवॉटरिंग करे तब तक अब एनजीटी ने एक नियम निकाल दिया दिल्ली जल बोर्ड ने रीप्रजेन्टेशन दे दिया कि submersiblecan करो, अरे पूरे दिल्ली में हो सकता है कि वॉटर टैबल नीचे जा रहा हो लेकिन आपको इतना तो बुद्धि लगाना चाहिये कि जहां पर वॉटर टैबल डेढ़ फुट पर आ गया है या दो फुट पर आ गया है आप वहां ijsubmersible बंद कर दिये अब

इन्होंने क्या किया है डीएम के माध्यम से एकदम से आर्डर करके सारा जो है submersible बंद कर दिया अब उसके चलते वॉटर टैबल और ऊपर आ रहा है जबकि वहां पर submersible का पानी लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो कम से कम उससे पानी मेन्टेन हो रहा था तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कल को भगवान ना करे हमारा जो दिल्ली है वो सेस्मिक ज़ोन फोर में आता है भूकंप के, अगर भगवान ना करे अगर 7 रियेक्टर का या 8 रियेक्टर का कोई एक झटका अगर भूकंप का आ गया तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस पर सदन इसको जो है संज्ञान में ले माननीय मंत्री जी भी लें और इस पर जो भी किया जा सकता है जल्द से जल्द किया जाये मैं ऐसा अनुरोध करता हूं धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष जी।

श्री अजय दत्तः अपनी विधानसभा का बोलना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं देख रहा हूं अजय दत्त जी ये मेरा काम है ये मेरा काम है अजय दत्तजी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने रोक दिया ना उसको, अरे मैंने रोक।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी ये मेरा काम है, आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आगे से एक सैकेंड, आगे से मैं अधिकारियों से प्रार्थना कर रहा हूं 280 में केवल विधानसभा से संबंधित विषय लें इसके बाहर कोई विषय हो तो उसे रिजेक्ट कर दें किसी भी, किसी भी पक्ष का।

श्रीमती राखी बिड़लाः आप बोलने ही ना दे अध्यक्ष जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी जितनी मर्जी बैरियर लगा लो सरकार के भ्रष्टाचार छुप नहीं सकते।

माननीय अध्यक्षः हां, कोई बात नहीं आप बोलिये, बोलिये, बोलिये, शुरू करिये, अब आप अपना विषय शुरू करिये ना, आप अपना विषय शुरू करिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः भ्रष्टाचार के मामले में सरकार इतना भागेगी ये तो ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आप शुरू करिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये तरीका ठीक नहीं है जवाब देना चाहिये, हंस रहे हैं शिक्षा मंत्री।

माननीय अध्यक्षः आप शुरू करिये ना जी।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आप शुरू कर रहे हैं कि नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं अपना विषय बोल रहा हूं अध्यक्ष जी देखिये, मेरा विषय बहुत जेन्युअन है सर और मैं आपके दरबार में अपनी दरख्वास्त लगा रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः बोलिये, शुरू करिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मेरे क्षेत्र में लगभग एक लाख आबादी का क्षेत्र है सैक्टर 18-19 का और वो पूरा तमाम क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेष रूप से उस क्षेत्र में आता है उसकी डैन्सिटी जो है पोपुलेशन वो मुझे लगता है दिल्ली में हाईएस्ट होगी उस एरिया में और वहां पर पिछले कई वर्षो से हमारा संघर्ष था, हम वहां पर एक विद्यालय बनवाना चाहते थे। डीडीए से दो एकड़ जमीन हमने लगभग 12, 14 साल पहले ली थी और दो एकड़ जमीन पर विद्यालय का निमार्ण हो, ये वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार एक विधायक के रुप में लगातार पर सरकार से संपर्क करता रहा, मिलता रहा अधिकारियों को और सदन में वो मामला उठाता रहा कि यहां विद्यालय की आवश्यकता है, विद्यालय बनाइये। 45 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर एक full fledged विद्यालय बनकर तैयार हुआ।

माननीय अध्यक्षः कौन से वर्ष में।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अभी ये।

माननीय अध्यक्षः वर्ष बोलों न, वर्ष लिखा नहीं आपने?

श्री विजेंद्र गुप्ताः वर्ष ये 2022-23 चल रहा है। 2022 में 21-22 में वो बनकर तैयार हुआ। मैंने खुद उस विद्यालय का कई बार निरीक्षण किया, उसको उसकी क्वालिटी को देखा कि अच्छा बने। लोगों में उत्साह था कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में जाएंगे, लेकिन एक घोर अन्याय हमारे साथ किया गया और वो हमारा अन्याय की पराकाष्ठा है कि उस विद्यालय में अब क्षेत्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। वो विद्यालय पहली कक्षा से नहीं होगा, उस विद्यालय का उस क्षेत्र के लोगों से सीधा कोई जुड़ाव नहीं रहेगा। इतना बड़ा अन्याय इस क्षेत्र में विद्यालय नहीं है। उसमें दिल्ली की सरकार का विद्यालय बने और उस क्षेत्र की जनता को उसमें दाखिला न मिले और वो भी विशेष रुप से जिनको सही रुप में आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, छोटे-छोटे बच्चे, पांच-पांच, छः छः साल के बच्चे पांच-पांच किलोमीटर दूर जाते हैं। आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे जब बड़ी बड़ी हाईवे क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है। सरकार ने एक फैसला ले लिया और arbitrary बिल्कुल एकदम वन साइडेड कि ये school of specialized excellence के होगा और यहां पर इंटरव्यू या जो भी आपका सिस्टम आपने अडोप्ट किया, पूरी दिल्ली से लोग वहां अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो मेधावी छात्राएं हैं वो दाखिला ले सकते हैं। आप खोलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक रेगुलर विद्यालय को बंद करके, उसको हटाकर अगर आप वहां पर एक्सीलेंस की बात करते हैं तो जो बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट है क्षेत्र की उसको अगर प्रभावित किया जाता है तो हम ये बिल्कुल बर्दास्त नहीं करेंगे। आप उसमें एक रेगूलर विद्यालय खोलिए ठीक है आप एक शिफ्ट चलाइये हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकेंड शिफ्ट में कुछ करना चाहें हमें उसमें भी

कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जनता के भावनाओं के अनुरुप इस सदन के समक्ष शिक्षा मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस विद्यालय में हमें रेगुलर पहली कक्षा से 12वीं तक का विद्यालय चाहिए और अगर सरकार ने हमारे मामले पर जरा भी कोताही बरती तो हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। हम चाहते हैं शिक्षामंत्री जी इस पर स्थिति स्पष्ट करें और हमें आश्वस्त करें कि हमारे क्षेत्र में उस पार्टिकुलर एरिया में आप उसका सर्वे करा लिजिए, आप उसका निरीक्षण करा लिजिए, आप उसकी रिपोर्ट मंगा लिजिए, कितनी उसकी पोपुलेशन है और वहां पर विद्यालयों की क्या स्थिति है।

माननीय अध्यक्षः हो गया कंप्लीट, धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं चाहता हूं शिक्षामंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। हो सकता है उनके पास हमारे हमें आश्वस्त करने के लिए कोई जवाब हो और जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप कोई ऐशोरेंस दे सकते हैं तो आप बताइये अभी, जनता जनता आपकी बात को सुनेगी।

माननीय अध्यक्षः अभी राखी जी बैठ जाइय, प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ताः लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास हमारी भावनाओं का कोई जवाब है। अध्यक्ष जी मेरा इतना कहना है।

माननीय अध्यक्षः आप भाषण दे रहे हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी मैं भाषण नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं, हो सकता है उनके पास कोई योजना हो।

माननीय अध्यक्षः वो देना होगा तो देंगे। आप बैठिए, आप बैठ जाइये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो बता दें, योजना बता दें।

माननीय अध्यक्षः नहीं क्यों बतायेंगे, उनकी इच्छा होगी बताएंगे। 280 में, नहीं बैठ जाइये आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभय वर्मा जी। अभय वर्मा जी मैं नाम बोल चुका हूं। श्रीमान अभय वर्मा। बैठ जाइये विजेन्द्र जी ये चीज नहीं है, तो ये सदन चल ही नहीं सकता फिर तो अगर हरेक के मंत्री उत्तर देने लगे, नहीं चलेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बैठ जाइये आप। अभय वर्मा जी चलिए।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अभय वर्मा जी। मैं नाम बोल चुका हूं। मैं मंत्री जी पर दबाब नहीं दे सकता हूं, उनको देना होगा देंगे। बैठिए। आप व्यक्तिगत मिलकर ले लिजिए।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी मुझे 280 नियम के तहत् बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बैठिय, बैठिये।

श्री अभय वर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग के मंत्री महोदय से सादर निवेदन

करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के साथ साथ समस्त दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन शुरू नहीं होने के कारण सीनियर सिटिजन के अंदर काफी रोज़ व्याप्त है।

आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द बुजुर्गों की पेंशन शुरू करवाई जाए ताकि हम अपने क्षेत्र के सभी आदरणीय सीनियर सिटिजन को पेंशन लगवा सकें। इसके अलावा गत दो वर्षो से जिन लोगों को सीनियर सिटिजन पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लगी हुई है, उनको पेंशन की राशि मिलने में भी तीन से चार महीना लग जाते हैं, जिससे उनके जीवन यापन में बहुत समस्याएं आती हैं। पेंशन को जल्द से जल्द प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच में जारी करने की कृपा की जाए और जिन लोगों की विध वा पेंशन और दिव्यांग पेंशन कार्यालय में अप्लाई की गयी है, उनकी भी वर्षो बाद भी पेंशन शुरू नहीं होती है और सरकारी कार्यालय से कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिलता, जिससे मेरे विधायक कार्यालय में प्रत्येक दिन अधिक से अधिक लोग अपनी पेंशन न शुरू होने के शिकायत करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी महोदय से आग्रह है कि जल्द से जल्द ऊपरोक्त चीजों को ठीक करें, जरूरतमंद लोगों को पेंशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र विश्वास नगर के अंतर्गत आने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत, सड़कों के डिवाइडर पर लगी ग्रीनरी की छटाई तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था

की ओर दिलाना चाहता हूं। विकास के नाम पार विकास मार्ग पर सड़कों के सौन्दर्यकरण का जो काम शुरू किया गया है उसमें पिछले दो साल से सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है। सच कहा जाए तो इस मुख्य सड़क के सौन्दर्यकरण की जो योजना है वह गलत तरीके से बनाई गयी है। पिछले दो सालों से क्षेत्र की जनता का इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क के सौन्दर्यकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान वजीरपुर विधान सभा के अंदर जो बस क्यू शेल्टर है, उन पर दिलाना चाहता हूं। ये बस क्यू शेल्टर न तो बहुत सालों से लग रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये भी है, जब सरकार लगाना भी चाहती है तो उसे अंदर टेंडर में कोई आता ही नहीं है क्योंकि जो विधान सभा के अंदर बस क्यू शेल्टर्स हैं, उनको वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनपर एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती? हमने विधायक फंड से पांच उसके ऊपर बस क्यू शेल्टर लगाए और वो बस क्यू शेल्टर्स में से आधा सामान चोरी हो गया।

पुराने जो बस क्यू शेल्टर्स हैं, उनको उखाड़ कर ले जाया जा रहा है। अब जो चोरी हो गया है तो फिर पुलिस से हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते। जैसा आपने कहा कि अगर आप भी पूछना चाहें कमिश्नर साहब से तो वो यहां आकर नहीं बतायेंगे। एलजी साहब ने अपना काम करना नहीं, नहीं तो वो पुलिस से पूछ लें कि कहां जाएं बुजुर्ग लोग, महिलाएं, प्रिगनेंट लेडी कहां

बैठे, बच्चे स्कूल की छूट्टी के बाद में कहां बैठें। पूरे पूरे उखाड़ दिए। कोई पुलिस यह बताने वाला नहीं है कि चोरी हो रही है तो कौन कर रहा है। लेकिन अगर विभाग उन्हें निकाल रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि विभाग विधायकों को कम से कम बताएं कि हम इनको निकाल कर ले जा रहे हैं, ये खराब हो गए हैं या टूटने वाले हैं क्या वजह है या नई लगाने वाले हैं। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है और लोग रोज आके हमसे बाते करते हैं कि हम कहां जाएं और कैसे बैठें क्योंकि अगर हम विधायक फंड से लगाएंगे भी तो इसमें काफी समय लग जाएगा इसे लगाने में तो माननीय मंत्री अभी आए नहीं हैं, लेकिन ये बात उन तक पहुंचे और वो इन्हें जरूर लगाएं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं वैसे मैं अपनी विधान सभा से बाहर की नहीं करना चाहता कि बार बार ये बात उठ रही थी किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दस में से जितने साथी बैठे हैं, छः को तो मौका मिल चुका है। आपके सवाल इनके लगे हुए हैं 280 में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये क्या हो रहा है। क्या बोल दिया उन्होंने। क्या बोला इन्होंने जिसमें विजेन्द्र जी क्या परेशानी हो रही है आपको। क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा। विजेन्द्र जी आप बैठिए। विजेन्द्र जी आप बैठिए। क्या बोला है, नहीं ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने, चलिए आप जारी रखिये।

श्री राजेश गुप्ताः सर दस में से छः को मौका मिल चुका है। माननीय नेता विपक्ष को आगे मौका मिलेगा। आठ साथी हैं, छः को मौका मिल गया, माननीय नेता विपक्ष आगे बोलेंगे और क्या रह गया। जितने साथी सबको मौका

मिल रहा है यहां तो किसी को मिल नहीं रहा इतना, तो ऐसा आप हाउस चला रहे हैं, इतना अच्छा चला रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बहुत अच्छा चला रहे हैं, ऐसे चलाते रहिए।

माननीय अध्यक्षः राजेश जी अपना विषय। धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ताः जब आप लगाओगे नहीं, तो आएंगे कहां से।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह बिष्ट जी। दो मिनट रूक जाओ आप विजेन्द्र जी, आप बार बार गलत बोल रहे हो। दो मिनट आप शांत रहिये। मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 280 के तहत् आपने लोकहित का महत्व और इस सदन में मैं अपनी विधान सभा करावल नगर के गंदे पानी की निकासी की ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा करावल नगर के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण विभाग के नालों के द्वारा गंदे पानी की निकासी की जाती है, जिसके संबंध में आपने भी अपने चैम्बर में एक अधिकारियों को बुलाकर के बैठक की थी। इस नालें में बंध ड्रेन, बिहारीपुर ड्रेन और उसके बाद इस्केप ड्रेन में गंदा पानी जाता है। अध्यक्ष जी यहां से ये जौहरीपुर जाकर के ये पानी गिरता है। मेरे द्वारा संबंधित विभागों से बार बार पत्र व्यवहार करने के वाबजूद भी डिमार्केशन के लिए अध्यक्ष जी पैसे भी दे दिए, डिमार्केशन के लिए उन्होंने इतिश्री की, जिसके कारण कि पूरे करावल नगर विधान सभा में गंदे पानी की वजह से लोगों से घरों में आना जाना बहुत बड़ी मुश्किल हों रही है, बीमारियां फैल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण विभाग व राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आदेश दें कि डिमार्केशन के अनुसार रोड, उस नाले की चौड़ाई की जाए, जिससे कि ये गंदे नाले की समुचित रुप से सफाई व्यव्स्था हो सके। क्षेत्र की जनता को गंदे पानी की समस्या से छूटकारा मिल सके, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, नरेश यादव जी। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में अभी एमसीडी चुनाव के बाद डीडीए के द्वारा 12 दिसम्बर को एक डेमोलेशन नोटिस दिया गया, जिसमें लगभग घोसिया कॉलोनी की लगभग हजार झुग्गियां और वार्ड नंबर 8 मेहरौली के अंदर लगभग तीन से चार हजार मकान तोड़ने का ये नोटिस है और इसमें 10 दिन का टाईम दिया गया अध्यक्ष जी कि 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपना इक्रोचमेंट हटा लें और अध्यक्ष जी ये इक्रोचमेंट मेहरौली आर्कोलोजिकल पार्क के नाम पर दी गयी है। ये जो वो नोटिस दिया गया है, जबकि अध्यक्ष जी, ये यहां पर जो लोग बसे हुए हैं, ये पिछले लगभग 40 से 50 साल पुराने लोग हैं और इनके पास में बाकायदा पेपर्स हैं, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहां मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें की बाकायदा रजिस्ट्री से मकान खरीदे हुए हैं। अचानक डीडीए ने एक डिमार्केशन कराई और डिमार्केशन में इन सारे एरिया को उसके अंदर लाद्डा सराय के अंदर ले आए और आर्कोलोजिकल पार्क के नाम पर अचानक ये डेमोलेशन ऑर्डर इश्यु कर दिया गया, जो बहुत ही गलत है।

अध्यक्ष जी, इसके लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और डीडीए के ऑफिस में भी जाकर हम लोग माननीय सोमनाथ भारती के थ्रु मिले सारे लोग और मेहरौली के लोग लगभग इसमें तीस से चालीस हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं और ये जो झुग्गियां हैं घोसिया कॉलोनी के, डुसिब में भी आती है अध्यक्ष जी, जबकि डुसिब का ये रूल है कि जहां झुग्गी वहां मकान और खुद बीजेपी ने भी एमसीडी चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान का हर जगह जाकर वोट मांगी थी और जैसे ही एमसीडी का चुनाव समाप्त हुआ पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के नोटिसेस इश्यु कर दिए गए और लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है और दिसम्बर के महीने में समझिए की कितने बुरी हालात है आज ठंड की और लोग परेशान हो रहे हैं।

अध्यक्ष जी, ये आर्कोलोजिकल पार्क जो हैं लद्दा सराय के नाम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये जितने भी मकान हैं अध्यक्ष जी, डीडीए ने अपने बाउंड्रीवॉल बना रखी है, एक हद डिसाइड कर रखी है, एक डिमार्केशन कर रखी है, उसके अंदर अंदर हैं। वो जो बाउंड्रीवॉल है, वो भी खुद डीडीए द्वारा बनाई गयी है और उस बाउंड्रीवॉल के साथ साथ में एक फिरनी रोड टाईप में, जो आउटर रोड भी कहते हैं, वो एक रोड भी बना रखा है, उसके अंदर के ये फ्लैट्स हैं। यहां पर अध्यक्ष जी झुग्गियां भी आती है, मल्टीस्टोरी फ्लैट्स भी आते हैं, यहां तक कि हमारे एक मशहुर क्रिकेटर चेतन शर्मा जी का फ्लैट भी इस एरिया में आता है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहां ये डेमोलेशन ऑर्डर दिया गया है तो अध्यक्ष जी ये बीजेपी जो है चुनाव के दौरान तो कहती है जहां झुग्गी वहां मकान लेकिन उसके तुरंत बाद गरीब लोगों के खिलाफ और इस तरह के षडयंत्र करके इस तरह ये नोटिस इश्यु किये जाते हैं।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा डेमोलेशन ऑर्डर है, इसको वापस किया जाए और ये बिल्कुल इलिगल है, अनैथिकल है और बिल्कुल लोगों के खिलाफ है। लोग यहां कम से कम तीस चालीस सालों पुराने लोगों के पास में डोकूमेंट्स हैं और ये डिमार्केशन भी बिल्कुल गलत की गयी है। इस डिमार्केशन को भी दोबारा से कराया जाए और जितनी भी झुग्गियां वहां पर लगी हुई है, वो डुसिब के थ्रु मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि डुसिब के थ्रु उनको अलग से जो मकान देने का प्रोविजन है, उसपर भी काम किया जाए और बीजेपी के भी जो इन्होंने ये नोटिस इश्यु किया, इसको मैं निंदा करता हूं कि इस तरह का नोटिस गलत दिया गया है। डीडीए के चैयरमेन एलजी है तो आप देखिए अध्यक्ष जी, एलजी साहब जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए तो मना कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी पेरलली हर डिपार्टमेंट के थ्रु वो आज दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रहे हैं और ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

माननीय अध्यक्षः हो गया प्लीज।

श्री नरेश यादवः और काफी ज्यादा एरिया है सही राम जी का भी एरिया है और अजय दत्त जी का भी एरिया है इसमें। छतरपुर से हमारे प्रताप सिंह तंवर जी का भी एरिया है, बहुत सारा एरिया है, जिसमें आज इस तरह के डेमोलेशन ऑर्डर दिए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः नरेश जी हो गया। हो गया प्लीज।

श्री नरेश यादवः मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये डेमोलेशन ऑर्डर निरस्त किया जाए और जो लोग जहां रह रहे हैं उनको वहां

पर रहने दिया जाए और उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही न की जाए और अध्यक्ष जी, जो अपने डोकूमेंट्स और जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनको वो रखने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री मान राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ये चार दिन पहले दिया था।

माननीय अध्यक्षः हां ये आया है सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र के पार्कों, सड़कों।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, जी आपने नियम 280 में क्षेत्र के मुद्दो को उठाने का मुझे मौका दिया। मैं पिछले काफी लम्बे समय से ये प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे फुटपाथ हैं या पार्क हैं, उसमें किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अनफोर्चुनेटली लगातार पार्कों के अंदर भी, फुटपाथ पर भी लगातार कब्जे हो रहे हैं। एमसीडी से कई बार मिल लिया, कई बार लिख कर दे दिया।

माननीय उपराज्यपाल महोदय को लिख कर दे दिया। कमिश्नर एमसीडी से बात कर ली, डीसी से बात कर ली, एसटीएफ में कई बार लगा लिया। सारे विभागों को लेकर कई बार विजिट कर ली, लेकिन ये अवैध कब्जे रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

दूसरा केवल ये अवैध कब्जे नहीं, हमारे दिल्ली सरकार का एक स्कूल बनना था। बहुत बड़ी जगह थी, उसमें तो बाकायदा कब्जा करके प्लॉट काट

दिए। प्लॉट काटके दो दो मंजिल, ढाई मंजिल के मकान तक बन गए और मेरे लम्बे प्रयास के बाद उसमें पुलिस की मदद मिली, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद मिली, उसके बाद वो ढाई-ढाई मंजिल तक के वो सारे कब्जे हमने हटवाकर और वहां स्कूल का निर्माण करवाया है शुरू अभी लगभग 50 करोड़ की लागत से, उसके लिए तो मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी का भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन दु:ख इस बात का है कि फुटपाथ के ऊपर एक मोहल्ला क्लीनिक पीडब्ल्युडी की उसपे बना था और हमारे हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बनाया था। एमसीडी ने उस बने हुए मोहल्ला क्लीनिक को पूरा जड़ से तोड़कर हटाया।

तो सरकार के द्वारा बनाए गए जो लोगों के इलाज के लिए काम आने वाला मोहल्ला क्लिनिक तो तोड़ा गया, उसको तो हटाया गया लेकिन जो फुटपाथों पर निरंतर लगातार कब्जे हो रहे हैं, मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद भी पार्कों में कब्जे हो रहे हैं, उनको हटाने के प्रति न एमसीडी गंभीर नजर आती है, न पुलिस गंभीर नजर आती है, न कोई दूसरा विभाग और यहां तक कि जो हमारे डूसिब और स्लम, जो स्लम विभाग है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पीडब्लूडी है, उनके भी ऑफिसर्स उतने गंभीर नजर नहीं आते इन कब्जों को हटाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाए कि जितने भी अवैध कब्जे रोड पर और फुटपाथ के अंदर और पार्कों के अंदर हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद 280 में बोलने का आपने मौका दिया। मैं आदरणीय अपने जल मंत्री, उप-मुख्यमंत्री हमारे सिसोदिया जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर करीब 30 परसेंट कॉलोनियों में तीसरे दिन पानी मिलता है और यदि बाकि 70 परसेंट में भी देखा जाए तो उनमें भी 2 घंटे, एक घंटे पानी मिलता है और पानी की समस्या को देखते हुए मैं आदरणीय अपने चेयरमैन, सौरभ भारद्वाज का भी ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र में एक यूजीआर बनाया जाए, जलाशय बनाया जाए जिससे कि क्षेत्र की पानी की समस्या हल की जा सके और वो लंबे समय ये समस्या चल रही है। तो मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि वो मेरे क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान करते हुए पानी की समस्या को हल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, स्वागत, बधाई।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमती बंदना कुमारी जी (अनुपस्थित)। श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में 72 लाख राशनकार्ड धारक हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 महीने से इन 72 लाख राशनकार्ड धारकों के लिए मोदी जी की सरकार के द्वारा जो राशन भेजा जाता है, वह राशन पिछले 2 महीने से राशनकार्ड धारकों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' का राशन दिसंबर का उठाया ही नहीं गया। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी। नेशनल फूड

सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 72 लाख राशनकार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, वह भी पिछले 2 महीने से उठाया नहीं गया। 'वन नेशनल वन कार्ड' 1,97,000 क्विंटल राशन भारत सरकार के गोदामों में पड़ा हुआ है कि दिल्ली सरकार उस राशन को उठाकर और बेचारे वो जो प्रवासी श्रमिक हैं उन तक पहुंचा दें, दिल्ली सरकार को अनेक रिमाइंडर केंद्र सरकार ने लिखे हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये जरूर चाहूंगा क्योंकि फुड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं कि आखिर क्या कारण है कि 1,97,000 क्विंटल राशन आप पिछले 3 महीने से उठा नहीं पा रहे है, इससे बड़ी किलता फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के पार्ट पर और दूसरी क्या हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, आधा दिल्ली सरकार उठाती है और आधा केंद्र सरकार उठाती है,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, जो आपने अब बोला हैं न, कुछ नहीं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इसी में है, वो ही बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः बिल्कुल वो ही।

माननीय अध्यक्षः न, मैं, मैं जो बोला, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अभी मैं बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः न, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ नहीं हैं ये चीजें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अभी, अभी देखिए।

माननीय अध्यक्षः न, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये मैं पढ़ देता हूं, पढ़ देता हूं ये।

माननीय अध्यक्षः जो इसमें लिखा है...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अगर इसमें वो नहीं हो तो मैं, मैं छोड़ दूंगा ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद।

माननीय अध्यक्षः ये मेरे पास जो पेज आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये है,

माननीय अध्यक्षः आपके पास तो कुछ भी नहीं। जो मेरे पास...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं अपनी बात को...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये आप ही का लिखा हुआ है, नीचे साइन है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हां, मैं लास्ट...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अलाउ नहीं...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास आया है,

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जो लास्ट है, वो मैं पढ़ देता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां, पढ़ दीजिए, लास्ट वाला पढ़ दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप मत बोलो, भई डायरेक्शन आप दोगे क्या, मुझे समझ नहीं आता।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्षः लास्ट पैरा पढ़ दीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: पिछले 6 महीने से राशन विक्रेताओं के कमीशन का भी भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है जबकि कमीशन की ये राशि उन्हें एडवांस में देनी होती हैं। इस तरह दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खाद्य-आपूर्ति मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द दिल्ली के राशनकार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध करवाने तथा राशन दुकानदारों का पिछले 6 महीने से बकाया कमीशन दिलवाने हेतु तुरंत कार्रवाई कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये 12 बजे तक मैं मैक्सिमम चाहता हूं पूरे हो जाए। अखिलेश पति त्रिपाठी जी। जो लिखा है वो बोल दीजिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अति-महत्वपूर्ण विषय में बोलने का, अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने का अवसर दिया। मेरे क्षेत्र में अध्यक्ष जी नजफगढ़ ड्रेन शक्ति नगर, रूप नगर, राणा प्रतात बाग, राजपुरा, गुड़ मंडी जैसे महत्वपूर्ण जगहों से होकर के गुजरती है। वजीरपुर भी, हमारे पड़ोसी साथी बैठे हुए हैं राजेश जी, बगल में हमारे सोम दत्त जी हैं, आगे तिमारपुर, दिलीप भाई बैठे हुए हैं, सब लोग एक इस नाले की दुर्गंध से बहुत पीड़ित थे, और ये दिल्ली के पर्यावरण को दूषित करने का एक बड़ा कारण

भी था। मैं आज इस सदन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री-आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दक्षिण कोरिया जाकर के जो सिओल का मॉडल 2018 में स्टडी करके आए और उस तर्ज पर जो नजफगढ़ ड्रेन का सफाई शुरू किया है, मैं माडल टाउन विधान सभा की तरफ से दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री- आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आज 90 परसेंट से ज्यादा उस नाले की जो दुर्गंध थी वो खत्म हो चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 20 तारीख का डेड लाईन दिया गया है, साढ़े तीन सौ नालों को, जो यमुना में डायरेक्ट गिरते थे उसको भी बंद करने का एक महत्वकांक्षी प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, उसके लिए भी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं।

आज ऐसा काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के एल.जी. साहब को भी उसमें कई बार बोट में घूमने जाने का अवसर मिल गया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आप आइये। लेकिन मुझे दुख होता है कभी-कभी एल.जी. साहब जब आते हैं, हम लोगों को बताते तो हम लोग भी और स्वागत करते।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे अच्छे आयाम अपने कामों से दिल्ली में दिए हैं। स्कूल के, शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए हैं। अभी पिछले दिन कल आ गए थे ये लोग, अरे हवा की बात करते हैं, हवा को साफकरने के साथ-साथ यमुना को साफ करने का प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है।...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: वो संकल्प पूरा हो रहा है आज दिल्ली में।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, मैं कुछ कह रहा हूं न।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: वो आपकी सरकार ने कभी पूरा नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, ये ठीक नहीं चलेगा ऐसे। मुझे समय की बर्बादी नहीं चाहिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: इसमें सर एक मिनट और लगेगा।

माननीय अध्यक्ष: आप अपने विषय को पूरा करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: तो आज सभी अपने एम.एल.ए. साथियों की तरफ से 58 किलोमीटर का जो ये गंदा मल वाला स्थान, बदबू वाला स्थान, जो हमारे न केवल लोगों की सांस में घुलकर के जहर का काम कर रहा था, ये नजफगढ़ ड्रेन का गैस, उसको खत्म करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, बल्कि यमुना के जो सफाई का मिशन है वो जोरशोर से चल रहा है, उसको भी सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने

एमसीडी में भाजपा को नकार दिया तो भाजपा डीडीए के माध्यम से, एएसआई के माध्यम से, दिल्ली की जनता के साथ बदला लेने का प्रयत्न कर रही है।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय मैं देख रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अरे भई मैं देख रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारती: अरे ये लिखा हुआ है भाई साहब, ये लिखा हुआ है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, मुझसे बात करिए। सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: ये सपेरे बनकर आए हैं अध्यक्ष महोदय आज यहां.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, मुझसे बात करिए। एक बार जो उन्होंने लिखा, वो-वो देखने दो, रूक जाओ।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारतीः नाग कहीं और है, सपेरा यहां आया है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, जो मेरे पास आया है, वो मैं आपको दिलवा रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारतीः वो ही, वो ही पढ़ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः उसमें नहीं बोल रहे हैं आप।

श्री सोमनाथ भारतीः वो ही पढ़ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरे पास इंगलिश में ये 5 लाईनें लिखकर आई हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः वही पढ़ रहा हूं, वही, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः हां, आइये।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, अब ये, मैंने लिखा तो है कि भई you are misusing agencies like DDA, ASI at the behest of BJP लिखकर तो दिया है ये, अंग्रेजी में लिखकर दिया है ये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपने दिया है, in the name of G-20.

श्री सोमनाथ भारती: In the name of G-20 attempts are being made to displace lakhs of poor people.

माननीय अध्यक्ष: यस।

श्री सोमनाथ भारती: Using agencies like DDA, ASI at the behest of BJP लिखा तो है इसमें, क्या लिखा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: लिख लिया भैया। अध्यक्ष महोदय...

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: अरे मुद्दे पर हूं मैं।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: नाग कहीं और है, सपेरा यहां आया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, आप पढ़िए, आप पढ़िए, प्लीज।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ये।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, ये डीडीए और एएसआई के द्वारा जो भाजपा दिल्ली के निवासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, मेरे पास डेमोलिशन ऑर्डर है जो 12 दिसंबर, 2022 का इशूड है। 7 दिसंबर, 2022 को दिल्ली की जनता ने मैसिव मैंडेट देकर के एमसीडी में भाजपा को हराया, आम आदमी पार्टी को लाया। अध्यक्ष महोदय, छोटी-मोटी जनसंख्या नहीं, करीब 1 लाख लोग को डिसप्लेस करने की इन्होंने, भाजपा ने डीडीए के जरिए करने की ठानी है। हर तरफ हाहाकार है। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर बगैर किसी डिमार्केशन के correct बेसिस पर इन्होंने कुछ नहीं तो, एक तो Ghosiya colony है जोकि झुग्गी झोपड़ी है, करीब 10 हजार झुग्गी झोपड़ियां वहां पर हैं, इन्होंने 17 में भी किया था एक प्रयत्न, तब इसको अरविंद जी के कहने पर रूकवाया गया था। अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने Ghosiya colony के साथ-साथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास मैप है, इस मैप में किस प्रकार से इन्होंने जो डिमार्केशन लाईन था, उसको अचानक शिफ्ट कर दिया, मतलब आप ये समझें कि इनकी अपनी दुकान है, इन्होंने डीडीए को अपनी दुकान मान रखी है।

(श्री सोमनाथ भारती द्वारा मैप दिखाया गया।)..

श्री सोमनाथ भारतीः इस दुकान के माध्यम से...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब ये। concerned है मैटर से। ऐसे नहीं चलेगा। दिल्ली बर्बाद हो रही है, आप लोग...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओम प्रकाश जी बैठ जाइये

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री सोमनाथ भारतीः ये लाईन अध्यक्ष महोदय...

माननीय अध्यक्षः हैं, मैप क्या उसमें लिखा जाएगा?

श्री सोमनाथ भारतीः इस लाईन को इन्होंने यहां से यहां मूव कर दिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, चलिए।

श्री सोमनाथ भारतीः मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने गैर आबादी इलाके से उठाकर के रेफरेंस लाईन आबादी में ले आए।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारतीः अरे मैं बोल तो रहा हूं वहां पर। अभी सपेरा वाला काम करो। अभी सपेरा वाला काम करो।

माननीय अध्यक्षः भई, ओमप्रकाश जी ये टोका-टाकी नहीं, प्लीज।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, डीडीए को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से...

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, अब कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती: कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूड कर देंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी डिमार्केशन जो करी है, जिन्होंने रेफरेंस लाईन फिर से ड्रा करा है, ये सारा flawed है और एक flawed प्रोसेस के जरिए इन्होंने करीब-करीब एक लाख लोगों को डिसप्लेस करने का ठाना है, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे, नंबर वन।

नंबर टू, 9 authorized कॉलोनिस, जिसमें कि 6 छतरपुर में हैं, 2 देवली में हैं, 1 साउथ डेली में है, जहां कि रजिस्ट्रेशन चल रही थी प्रॉपर्टियां की और अचानक इन्होंनें ये डिक्लेयर कर दिया कि भई जो अन-ऑथराइज कॉलोनियां हैं वो इलीगल करार हो गई, कहते हैं कि भई वो रिज के एरिये में आ गया। जो कॉलोनियां 1965 से बसी हुई हैं, 60 साल, 70 साल से बसी हुई हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, लोगों के बच्चे आसपास के स्कूलों में जा रहे हैं, अचानक.

माननीय अध्यक्ष: भई अब कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, औरों का समय भी देखिए।

श्री सोमनाथ भारती: एक सैकंड मैं बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप औरों का समय नहीं देखेंगे, मामला खराब हो जाएगा।

श्री सोमनाथ भारतीः आखिरी लाईन। आखिरी लाईन। मैं अध्यक्ष महोदय चूंकि मेम्बर डीडीए हूं, आपने बनाकर भेजा है वहां अपने सदन से, इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि डीडीए को पूरे राजनैतिक रूप में भाजपा दुरूपयोग कर रही है और करीब-करीब 4 से 5 लाख लोगों को डिसप्लेस करने की उन्होंने ठानी है। और अब मैं आपके जरिए डीडीए को कहना चाहता हूं कि भई जब तक केजरीवाल जी दिल्ली में हैं तब तक एक भी आदमी को विस्थापित नहीं होने देंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रीति जी, प्रीति जितेंद्र तोमर, लास्ट है ये बस।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब हो गया। अरे एक महिला को...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं अब, 12 बज चुके है। नहीं, एक महिला का इसमें आया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, महिलाओं के साथ अन्याय कर दें, एक महिला का आया है, उसको बोलने नहीं दोगे। एक महिला का आया है उसको नहीं बोलने दोगे। आप बैठ जाइये अब। तोमर जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिए आप, बोलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपका नहीं छोड़ा है, तीन छोड़े हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हां। ये मेरी मर्जी है जिससे बुलवाऊंगा। बैठ जाइये।

...व्यवधान...

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष महोदय....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये महाजन जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, सभी सदस्य बैठ जाइये। शुरू करिए। बैठिए। बैठ जाइये।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: हां, बोलिए।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष महोदय, मेरे त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में डीटीसी के करीब 20 बस क्यू शेल्टर हैं परंतु उनमें से 13 बस क्यू शेल्टर पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, बस उनके अवशेष बाकी है ताकि लोगों को पता

रहे कि यहां पर डीटीसी का बस स्टैंड है। बस क्यू शेल्टर न होने की वजह से यात्रियों को गर्मी और बारिश के मौसम में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय परिवहन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपया मेरे त्रिनगर विधान सभा में जल्द से जल्द बस क्यू शेल्टर बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। देखिए, जितेंद्र जी सुन लीजिए अब, उठिए नहीं, मुझे मालुम है, मैंने देख लिया, आपका बीसवें नंबर पर है, लिस्ट उठाकर देख लीजिए। आप नाजायज शोर मचा रहे हैं। एक सेकंड बैठ जाइये, बीसवें नंबर पर है। तोमर जी का नंबर, प्रीति तोमर जी का उन्नीसवें नंबर पर है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बस बैठ जाइये अब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये। एक महिला भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। एक महिला को, और आपका बीसवें नंबर पर है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम 54, आतिशी जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः न, मैं नहीं बुलवा रहा हूं बीसवां नंबर है, 12 बज चुके है, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। कुछ नहीं होगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे उससे पहले, उससे पहले सोलवां है, सतहरवां है, अठारवां है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, किसी को नहीं बुलवा रहा हूं अब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः न, बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम 54, श्रीमती आतिशी जी, माननीय सदस्य, बच्चों की शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो रहे वैधानिक तथा अवांछित अवरोधों और दखलअंदाजी के संबंध में माननीय उप-मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

...व्यवधान...

श्रीमती आतिशीः माननीय अध्यक्ष महोदय...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये। बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये मेरा अधिकार है, जिसको मैं चाहूंगा दूंगा। ये मेरा अधिकार है, जिसको मैं चाहूंगा दूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं सदन के बीच में बोल रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अगर एल.जी. अपने अधिकार का नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं भी कर सकता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं बिल्कुल।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये शोर-शराबा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड अलाउ नहीं करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये शोर-शराबा मैं अलाउ नहीं करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं ये शोर-शराबा बिल्कुल नहीं पसंद करता। ना मैं चाहता हूं। मैंने बिजनेस एक्सेप्ट किया है मैं उसी पर चलूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बिल्कुल मैं उसी पर चलूंगा। नहीं कोई नहीं कोई जरूरत नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं है।

श्री कुलदीप कुमारः ये मोदी जी के चेले हैं और ये महिला विरोधी हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ये शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जहां लोकतंत्र का गला एलजी घोंट सकता है तो लोकतंत्र की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती।

श्री कुलदीप कुमारः ये गुंडागर्दी पर बात करेंगे खाली।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जहां लोकतंत्र एलजी गला घोंट सकता है

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वहां लोकतंत्र की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये। मैं माननीय सदस्यों से विपक्ष के सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः मार्शलस मार्शलस आइए। ले के जाएं। बाहर ले के जाएं। मैं नाम बोल रहा हूं। अजय महावर, ओमप्रकाश शर्मा, जितेन्द्र महाजन सभी को, तीन सदस्यों को छोड़कर, जो वैल में हैं बाहर करिए। ले जाइए इनको। मैंने बोल दिया है। जो वैल में हैं उनको ले के जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एलजी की अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध विपक्ष कुछ नहीं सुनना चाहता।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां भ्रष्टाचार का मुददा है। भ्रष्टाचार का मुददा। चलिए भ्रष्टाचार। ले के जाइए। ले के जाएं सब जल्दी से। समय खराब हो रहा है सदन का। जाइए। उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ। ना मैं कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने बोल दिया है, जो मैंने निर्णय लिया है उसी पर चर्चा होगी। मैंने जो निर्णय लिया उसी पर चर्चा होगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं। आप ले के जाइए। उठा के ले के जाइए। मैं किसी पर बहस नहीं करवाना चाहता।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे मालूम है क्यों बंद हैं, मुझे मालूम है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः केंद्रीय सरकार की गुंडागर्दी की वजह से बंद है। ले जाइए। ले के जाएं। हां बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। ले के जाओ इनको जल्दी से। ना, मैं कोई बहस नहीं चाहता। नहीं कोई बहस नहीं चाहता हूं। पहले अपने आका से जा के बात करो। पहले अपने आका से जाके बात करो। हां छोडिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चर्चा मैं नहीं करवा रहा, बात खत्म हो गई। नहीं, मैं नहीं बहस करवा रहा। ले के जाइए बाहर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आपको बैठना है तो बैठ जाइए। ये जो माननीय सदस्य, अभय वर्मा को भी ले के जाइए।

श्रीमती राखी बिरलाः इन्हीं को पहले ले के जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अनिल बाजपेयी जी को ले के जाइए और ये सदस्य आज पूरे दिन के लिए ये माननीय सदस्य जो बाहर किए हैं पूरे दिन के लिए जब तक सदन चलेगा तब तक बाहर रहेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं छोड़ दीजिए। तरीका है, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है जो एलजी साहब कर रहे हैं? जो एलजी साहब कर रहे हैं ये कौन सा तरीका है? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो एलजी साहब कर रहे हैं ये कौन सा तरीका है? हां जाइए। छोड़ जाइए, कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आतिशी जी।

श्रीमती आतिशीः धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं कोई विपक्ष को समय नहीं दे रहा हूं चर्चा के लिए। आतिशी जी।

श्रीमती आतिशीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज स्पष्ट कर दी कि शिक्षा पर चर्चा वो सहन नहीं कर सकते हैं कि जहां पर शिक्षा की बात शुरू हुई जहां पर सरकारी स्कूलों की बात शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हल्ला शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये नहीं

चाहते हैं कि दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो ये चाहते हैं कि दिल्ली का और देश का हर बच्चा सिर्फ इनकी झूठी वाटसअप यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहे इसलिए इतना हल्ला कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में ये एक बहुत गंभीर मुददा दिल्ली के सामने और देश के सामने आया है कि किस तरह से दिल्ली में एलजी महोदय दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं जिन्हें ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा था एलजी महोदय ने टीचरों कि फिनलैंड की ट्रैनिंग पर रोक लगा दी ये बहुत शर्म की बात है और आज पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि जब दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को विदेश ट्रैनिंग के लिए भेजना चाहती है तो एलजी साहब उसमें क्यूं अडंगा डाल रहे हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो यहां से चले गए कि आप 2015 से पहले का समय याद करिए? हो सकता है कि आप सरकारी स्कूल में ना पढ़े हों, हो सकता है आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढे हों लेकिन 2015 से पहले आप पूछिए जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढते थे कि स्कूलों का क्या हाल होता था। वहां पे बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होती थी, कुर्सी नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था। टीचर अक्सर क्लासरूम से बाहर होते थे। ये होता था सरकारी स्कूल का हाल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था जब तक उसकी मजबूरी ना हो और उसके पास एक पैसा ना हो के वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज सके, पर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई है। मुझे गर्व है इस बात का कि हम एक ऐसी विधानसभा में बैठे हैं जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को देती है ये हमारे लिए गर्व की

बात है। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जिसने अपना 25 परसेंट बजट शिक्षा के लिए रखा और सरकारी स्कूलों को सुधारा। हमने नई बिल्डिंग तो बनाई, नए डेस्क लिए, नये टेबल कुर्सियां लीं, बिल्डिंग को शानदार बनाया लेकिन हमने टीचर्स की ट्रेनिंग में भी बहुत सुधार किया, हो सकता है बहुत लोग ये जानते हों कि दिल्ली सरकार अपना 25 परसेंट बजट शिक्षा को देती है लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि टीचर ट्रेंनिग का बजट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दस गुणा बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले साल भर में मात्र दस करोड़ रूपये टीचर ट्रेनिंग पर लगते थे जब कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 50 हजार से ज्यादा टीचर हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई जब से हमारे माननीय उपमुख्य मंत्री मनीष सिसौदिया जी शिक्षा मंत्री बने दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रूपये से ज्यादा सालाना टीचरों की ट्रेनिंग पर खर्च करना शुरू किया। इससे सरकारी स्कूलों में बदलाव आया है। पहले सुनने में आता था कि और राजनीतिक दल होते थे उनके मंत्री विदेश घूमने जाते थे उनके एमएलए विदेश घूमने जाते थे। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने टीचरों और प्रिंसीपल को विदेश भेजा कि जाओ और दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल देखकर आओ और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वैसा बनाओ। हमने अपने टीचरों को हार्वड यूनिवर्सिटी भेजा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा जब दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर और प्रिंसीपल इन देशों में अच्छे अच्छे स्कूल देख के आते हैं तो वो प्रेरणा ले के आते हैं कि हम भी अपने स्कूल को ऐसा बना सकते हैं कि हम भी दिल्ली के गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास ऐजूकेशन दे सकते हैं। आज ये बहुत शर्म की बात है कि माननीय एलजी महोदय दिल्ली सरकार

के जो स्कूल के टीचर हैं उनको फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इससे नुकसान किसको होता है इससे नुकसान दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढने वाले 18 लाख बच्चों को होता है जो दिल्ली के गरीब परिवारों से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब को आम आदमी पार्टी से बहुत नफरत है, हमें पता है। उनको अरविंद केजरीवाल जी से बहुत नफरत है हमें ये भी पता है लेकिन उनकी नफरत इतनी हद पार कर गई है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से नफरत की वजह से वो दिल्ली में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों से भी नफरत करने लग गए हैं ये आज पूरे दिल्ली के लिए और देश के लिए दुख की बात है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताउं आपको कि जो आर्डर उन्होंने पास किया कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को फिनलैंड नहीं जाने देंगे ये बिल्कुल गैर कानूनी है और बिल्कुल गैर संवैधानिक है। दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार की क्या पावर्स हैं उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ ने किया है। एलजी साहब के पास क्या पावर हैं उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ ने किया है और ये आर्डर है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ का वो एक नहीं दो-दो जगहें हैं उस आर्डर में स्पष्ट तौर में ब्लैक एंड व्हाईट में कहता है The Lt. Governor has not been entrusted with any independent decision making power ये para 284 section 17 में ये आर्डर कहता है और बिल्कुल यही बात para 475 section 20 में भी बिल्कुल यही बात कहता है कि there is no independent authority vested in the Lt. Governor to take decisions तो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संविधानिक तरीके से आज एलजी साहब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को दिल्ली की परिवहन व्यवस्था

को धवस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी एलजी साहब से एक निवेदन करना चाहूंगी मैं एलजी साहब को ये याद दिलाना चाहूंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए पूरी दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान में लिखा है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ ने किया है उस फैसले का पालन करें वरना ना सिर्फ दिल्ली की जनता, पूरे देश के लोग एलजी महोदय को मफ़ नहीं करेंगे, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आज इस फिनलैंड में टीचर्स को भेजने के विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल भी हम लोग एलजी महोदय के दफ्तर में उनसे मिलने गए। सभी विधायक साथी, मुख्यमंत्री जी, उपमुख्य मंत्री जी सभी मंत्रीगण हमारे साथ थे। हम यहां विधानसभा से पैदल एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब ने मिलने का समय नहीं दिया। हम उनसे यही पूछना चाहते थे कि वे जिस तरीके से अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो शक्तियां उनके पास हैं नहीं उनको क्या लगता है कि वो शक्तियां कहां से उनके पास आ रही हैं। जैसा कि अभी अभी आतिशी जी ने भी बताया कि शिक्षा ही नहीं ऐसे बहुत सारे मामले हैं हम अपनी समितियों के अंदर भी देख रहे हैं कि जो जो मामले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं चाहे वो पेंशन से संबंधित हों, चाहे वो जलबोर्ड से संबंधित हों, चाहे वो अस्पतालों से संबंधित हों, चाहे वो मौहल्ला क्लीनिक से संबंधित हों। सभी मामलों में हमने देखा कि किसी ना किसी अफसर ने उन कामों को रोकने

की कोशिश की है और आज संविधान पीठ में ये मामला बहस में चल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर और वहां पर चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने एक उदाहरण देकर पूछा है कि अगर कोई अफसर चुनी हुई सरकार के मुताबिक जनता के भले के काम नहीं करता और उदाहरण के तौर पर उन्होंने किसका नाम दिया उन्होंने कहा उदाहरण के तौर पर फाइनेंस सैक्रेट्री अगर काम नहीं करता। ये कोई इत्त्तेाक नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्यूं उदाहरण भी फाइनेंस सैक्रेट्री का आया। ये उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस आफ इंडिया भी जान रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के काम रोकने का जो ठेका है वो इस वक्त जो है फाइनेंस सैक्रेट्री ने उठा रखा है। ये उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस कह रहे हैं और यहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र शोर मचा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मतलब ये दो तरीके की पोलिसी साथ-साथ चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपोंइटिड एलजी साहब और उनके इशारे पर जो उनके अफसर काम करते हैं वो लोग काम रोक रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो जब एलजी साहब ही सारे के सारे काम करने का ठेका ले रहे हैं तो भई उन्हीं से पूछिए कि काम क्यों नहीं हो रहा और अगर चुनी हुई सरकार से आपको पूछना है कि काम नही हो रहा तो चुनी हुई सरकार की शक्तियों के अंदर जो आप दखलअंदाजी कर रहे हैं जो आप टांग अड़ा रहे हैं वो टांग अड़ाना बंद करें। अध्यक्ष जी, मैं एलजी साहब कि वो दोनों फाइल नोटिंग लाया हूं जिसमें उन्होंने फिनलैंड जो टीचर्स जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एक उनका ओबजैक्शन है अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अक्सर अनपढ़ होते हैं तो मेरे गांव

के अंदर दो चार लोग बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के मैं तो जानता हूं कह रहे भाई तुम एक बात बताओ तुम टीचरों को थाइलैंड क्यों भेज रहे हो, मैंने कहा भइया थाइलैंड नहीं भेज रहे फिनलैंड भेज रहे हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाइलैंड से बाहर सोच ही नहीं पा रहा वो वहीं फंसा हुआ है। हम उन्हें बोल रहे हैं वो जो है वो फिनलैंड जा रहे हैं अब एक मैंने देखा टवीटर पे लिखा हुआ है। मेरे टवीटर पर ही किसी ने जवाब दिया है कि भई एक बात बताओ फिनलैंड में ऐसी क्या खास बात है। अब ये कोई इनको कैसे बताए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है तो या तो दिल्ली की होती है या फिनलैंड की होती है। दो ही मॉडल हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनकी चर्चा होती है तो हम उनसे कुछ सीखें वो हमसे कुछ सीखें। ये होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं और वहां पे शिक्षक जाएंगे उनके जो अच्छे मॉडल हैं शिक्षा के उसको हम सीखेंगे उसको यहां पर ले के आएंगे तो हम भी कुछ चीजें सीखेगें। अब एलजी साहब का देखिए एलजी साहब के पास पहली बात तो कोई शक्तियां नहीं हैं कि वो सरकार के चुनी हुई सरकार के किसी भी डिसीजन के ऊपर सवाल उठाएं। उनके पास सिर्फ दो आप्शन हैं क्या दो आप्शन हैं जो संविधान में दिए हैं वो ये हैं या तो वो कहें कि भई ये चीज मुझे मंजूर है ये पास हो गई या वो ये कहेंगे कि इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा राष्ट्रपति जो है इसका निर्णय लेगें। उनके पास अपनी बात का कहने का अपनी स्वयत किसी डिसीजन का उनके पास कोई इंडीपेंडेंट अथोरिटी नहीं है किसी भी चीज के ऊपर वो फैसला दें कि ये सही है ये गलत है। अब इसके अंदर देखिए इसको हमारी भाज़ा में कहते थे नुक्ताचीनी करना मतलब

आपको अगर किसी के काम में कोई कमी निकालनी हो तो आप पूरे दिन निकालते रहिए। आप पहली बार जब इनके पास फाइल गई कि भई कुछ टीचर जो हैं उनको फिनलैंड भेजा जा रहा है तो पहले उन्होंने क्या कहा कि भई डीओपीटी गाइडलाईनस के कंपलाईस देखी जाए? क्या ये टीचर वो ही तो नहीं जिनको पहले भेजा गया था? इनको कूलिंग आफ पीरड दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा फिर दूसरा इन्होंने कहा कि एससीआरटी ये बताए कि जो ऐजेंसी इनकी ट्रेनिंग के लिए वहां इनको भेज रही है उस ऐजेंसी के क्या credential हैं उस ऐजेंसी ने पहले इस तरीके की ट्रेनिंग की है या नहीं की है मतलब बिना बात के सवाल और फिर ये प्रपोजल जो है वापिस भेज दिया फिर इसके बाद इनके इन सवालों का जवाब जो है अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि एलजी ने प्रश्न पूछा और उसका जवाब वहीं दे दिया ऐसा नहीं होता। एलजी साहब ने अगर प्रश्न लगाया तो ये फाइल जो है महीनों तक घूमती हुई जो है नीचे के अफसर तक पहुंचेगी। वो इस प्रश्न का जवाब देगा और ये फाइल फिर एक महीना लगाते हुए ऊपर पहुंचेगी एलजी साहब के पास। अब एलजी साहब ने क्या किया एक और इसमें प्रश्न लगा दिया वो वाले प्रश्न खत्म हो गए उनके । अब नए प्रश्न आ गए अब उनके प्रश्न ये आ गए कि भई ये जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इससे पहले भी ट्रेनिंग दी गई है क्या उन ट्रेनिंगस का कोई कॉस्ट बेनिफिट ऐनेलिसिस किया गया है नहीं किया गया वो किया गया है और नहीं किया गया है तो करके मुझे दो पहली बात ये। दूसरी तो क्या इस तरीके की ट्रेनिंग जो है हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, हो सकती है, नहीं हो सकती है मतलब ये बेफिजूल के सवाल हैं। भई अगर हिंदुस्तान में ही फिनलैंड होता तो हिंदुस्तान में ढूंढ लेते, ये कोई पूछने वाली बात है कि

क्या हिंदुस्तान में फिनलैंड है। हिंदुस्तान में फिनलैंड नहीं है। फिनलैंड फिनलैंड में है तो हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान में हो जाती है ट्रेनिंग। अब फिनलैंड जाना पड़ेगा मतलब बेफ़िजूल के सवाल और एलजी साहब सिर्फ इस सवालों को क्यों लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इन कामों के अंदर रोड़ा अटकाया जाए। अध्यक्ष जी, ये कोई साधारण से साधारण अफसर भी जानता है, कोई छोटा बाबू भी जानता है कि किसी काम को आपको रोकना हो तो उसके अंदर चार प्रश्न लगा दो और उस फाइल को दोबारा चला दो। उन प्रश्नों को जवाब आएगा फिर चार प्रश्न और लगा दो और उस फाइल को आगे चला दो तो ये जो एलजी साहब कर रहे हैं मुझे पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये ही काम अनिल बैजल साहब करते थे और उसी कारण ही ये हारे क्योंकि दिल्ली की जनता देखती रहती है कि भई इनके पास काम तो कोई है नहीं। लोगों ने काम अरविंद केजरीवाल जी को दिया ये सिर्फ काम के अंदर टांग अड़ाते हैं तो इसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अनिल बैजल साहब का क्या है वो तो अपने जीके की कोठी में दोबारा से मजे में हैं। भारतीय जनता पार्टी यहीं अपोजीशन मैं बैठे हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब ये विनय सक्सैना जी आए हैं ये पूरे इस तरीके के काम करेंगे रोड़े अटकाएंगे फिर जा के वो अपना कहीं चले जाएंगे ये फिर अपोजीशन में बैठेगें, क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे इसी बात पर चिढती है कि भई तुम कामों के अदंर टांग क्यों अड़ाते हो?

अब ये आज जो है सारे के सारे काले कपड़े पहनकर आए। मुझे वो फ़िल्म याद आई, अध्यक्ष जी बहुत पहले आई थी नगीना फ़िल्म थी श्रीदेवी की। उसमें जो अमरीशपुरी थे वो ऐसे काले कपड़े पहनकर जो है बीन लेकर घुमते

थे, वो ये पहनकर आए। मतलब मैं इनको बताऊं अध्यक्ष जी अगर ये अपनी फोटो अपने ही पोते–पोती को दिखा दें वो भी डर जाएं की बाबा ये क्या बन गए। हैं मतलब कोई अच्छे काम करो, मतलब कर्म तुम्हारे बुरे, कपड़े तुम्हारे बुरे शक्लें तुमने और ऐसी बना ली। ये चीज ठीक नहीं है और हमारे यहां भी कमजोर दिल के लोग हैं हम भी डर सकते हैं जिस तरीके के वो हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। तो अध्यक्ष जी, ये सारी बात मैं अपनी समराइज करूंगा और समराइज करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने इलैक्टीड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को खराब करने की कोशिश की है, ये कोशिश इन्होंने 2015 में दिल्ली में शुरू की। हम लोग कहते थे कि देखये एल जी इंटरफेयर कर रहा है, अजय माकन साहब तालियाँ बजाते थे, कहते नहीं सही कर रहा है। फिर उन्होंने ये काम पुडुंचेरी में करना शुरू किया तो काँग्रेस वाले कहते थे हाँ ये तो गलत हो रहा है। उसके बाद अब ये बंगाल में हुआ, उसके बाद अब ये तमिलनाडू के अंदर हो रहा है, अब ये हर राज्य के अंदर ये इंटरफेरेंस हो रहा है और ये इलैक्टीड गवर्नमेंट का जो institution है उस institution को बबार्द करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सीबीआई को खराब किया, इन्होंने ईडी को खराब किया, इन्होंने दिल्ली पुलिस को खराब किया और अब इनके टारगेट पर ज्यूडीशियरी है अध्यक्ष जी। अब आप देखिये की रोजमर्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ज्यूडीशियरी को बदनाम करने के अंदर लगे हुए हैं, ज्यूडिशियरी के अंदर कमियाँ निकालने के लिये लगे हुए हैं और इस हाउस के माध्यम से मैं ये चिंता जताना चाहता हूं कि ज्यूडिशियरी के institution जो खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, वो बहुत गलत precedence है, ये इकलोता

ऐसा institution देश में बचा है जिसके ऊपर देश को विश्वास है। जिस तरीके के संकेत केंद्रीय सरकार ज्यूडिशियरी को दे रही है, दादागिरी दिखा रही है, कह रही है भई कोलेजियम में भी हम आएंगे, अब जज भी तुम्हीं बनाओगे तो तुम्ह ही बन जाओ ना जज। मोदी जी एक दिन कहें की आज मैं रैली करूंगा, अगले दिन मैं चीफ जस्टिस हूं। वही बन जाएं सबकुछ, वही कर लें सबकुछ ऐसे कोई ना होता अध्यक्ष जी। कोई institution तो रहने देंगे। तो ये institution जो है जिसको ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिये मैं चिंता जताना चाहता हूं और अध्यक्ष जी अब जो है आपकी अनुमति से इस सदन की अनुमति से मैं जो है एक रैजूलुशन लाने की जो है परमिशन चाहता हूं। तो मैं एक बारी पढ़ लेता हूं, परमिशन के लिये। अध्यक्ष महोदय, तो अध्यक्ष जी मैं आपसे जो है इसकी परमिशन मांगना चाहता हूं कि मैं जो है ये रेजूलुशन हाउस के सामने रख सकूं।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव पढ़ दिया आपने, पूरा पढ़ दीजिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं सौरभ भारद्वाज, अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे ध्यानाकर्षण के विषय में संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय सदस्य द्वारा परमिशन मांगने का,

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, सदन द्वारा श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

अब सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। यह सदन उप-राज्यपाल महोदय द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिये फिनलैंड भेजे जाने से रोके जाने के, उनके कदम की कड़ी निंदा करता है। दिल्ली के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आदि विषयों पर काम करने के लिये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चुनी है। अगर दिल्ली के लोगों की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार Delhi के स्कूलों के शिक्षकों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाना चाहता है और इसके लिये इस विधान सभा में बजट भी पास किया हुआ है तो ऐसे में उप-राज्यपाल महोदय के पास संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता कि वह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये फिनलैंड जाने से उन्हें रोके। देश के संविधान में शिक्षा दिल्ली विधान सभा को हस्तांतरित एक विषय है। संविधान में दिल्ली के संदर्भ में केवल तीन विषय जो की हैं पुलिस, पब्लिक ओर्डर और जमीन। संघीय सरकार द्वारा निर्णय लेने के रिजर्व रेखे गए है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी संविधान पीठ में ये व्यवस्था दी है कि दिल्ली के संबंध में ऊपरोक्त तीन रिजर्व विषयों को छोड़कर शेष विषयों को छोड़कर शेष विषयों

पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है और मैं निर्णय के बारे में बात दूं अध्यक्ष जी ये निर्णय जो है संविधान पीठ में 4 जुलाई, 2018 में अपने आदेश पैरा 284 बिंदु संख्या 17 में लिखा था, अंग्रेजी में अध्यक्ष जी मैं बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ना चाहता था उसका अनुवादन नहीं किया है "There is no independent authority vested in the Lt. Governor to take decisions save and accept on the matters where he exercises his discretion as a judicial or quasi- judicial authority under any law or has been entrusted with the powers by the President under article 239 on the matters which lie outside the competence of Govt. of NCT Delhi और अध्यक्ष जी इसी संविधान पीठ ने अपने 4 जुलाई, 2018 के आदेश में पैरा नम्बर 475 बिंदु संख्या 20 में लिखा है The meaning of aid and advice employed in the article 239 AA(4) has to be construed to mean that the Lt. Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers and this position holds true so long as the LG does not exercise his powers under the proviso to clause (4) of Section 239 AA. The Lt. Governor has not been entrusted with any independent decision making power. He has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or he is bound to implement the decision. तो अध्यक्ष महोदय ये जो है ये संविधान पीठ की दो पैराग्राफस मैंने पढ़े और अब मैं आगे जो रेजुलूशन पर आ रहा हूं। संविधान में दी गई व्यवस्था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ द्वारा इस संबंध

में दिए गए निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। उप-राज्यपाल महोदय के पास इस संबंध में निर्णय लेने के लिये कोई संविधान में कोई ऐसी शक्ति नहीं गई है। इसके बावजूद उप-राज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का कदम न सिर्फ असंवैधानिक है ये बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। माननीय उप-राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के आदेश का उल्लंघन करना और संविधान को ना मानना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से सहमति करता है कि अगर हम स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो इसके लिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शिक्षकों को भी विश्वस्तरीय ट्रेनिंग मिले। आज सारी दुनिया में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये दुनियाभर के देश फिनलैंड में किए गए शिक्षा सुधारों से प्रेरणा ले रहे हैं। यह सदन दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के कदम का समर्थन करता है। साथ ही यह सदन उप-राज्यपाल महोदय से निवेदन करता है कि वह भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन से बचे और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, धन्यवाद अध्यक्ष जी ये रैजुलूशन सदन के सामने है बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः संकल्प पारित करना, अब श्री कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो मेरे बाबा साहब का संविधान है। अध्यक्ष जी, बाबा साहब अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया था और यह कहा था कि अब इस देश में जो भी सरकार बनेगी वो जनता के वोट के अधिकार से सरकार बनेगी। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि आज फिर दोबारा से उस चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने से रोकना, कामों में अडंगा अड़ाने का काम जो आज उप-राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रस्ताव अभी भाई सौरभ भारद्वाज जी ने सदन के सामने रखा की किस प्रकार से शिक्षकों को जो फिनलैंड जाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी थी, भेजने का काम करना था उसको रोकने का काम उप-राज्यपाल महोदय ने करने का काम किया। क्योंकि अध्यक्ष जी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था थी, कैसे सरकारी स्कूल थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से आप पूछ लीजिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के क्या हालात थे।

अध्यक्ष जी मैंने खुद 2008 में बारहवीं पास की थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल से। तो मैं तो उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है क्या व्यवस्था थी वहां पर। आज अध्यक्ष जी इतना बड़ा बदलाव इन स्कूलों के अंदर आया है और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि वो बदलाव इसलिये आया क्योंकि आज हमारे शिक्षक बाहर विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और जब वहां ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो ट्रेनिंग को लाकर स्कूल में इम्पलीमेंट करते हैं, बच्चों

में सुधार होता है, उनकी एजूकेशन में सुधार होता है और आज वो गरीब का, मजदूर का, रिक्शेवाले का, दलित का, सफाई कर्मचारी का बच्चा एक बड़ा अफसर बनने का सपना देख पाता है इसकी बदोलत क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ये सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो शिक्षा मंत्री जी भी हैं वो सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं। क्योंकि उनको चिंता है उन बच्चों के भविष्य की। क्योंकि उनको चिंता है उन बच्चों की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा की और इसलिये ये आइडिया आते हैं, इसलिये इनको इम्पलीमेंट करना पड़ता है। आज से पहले अध्यक्ष जी मैंने कभी नहीं सुना की कोई सरकार किसी को फिनलैंड भेज रही हो, कोई कैंब्रिज भेज रही हो, कोई हार्वड भेज रही हो, उनको पता नहीं था अध्यक्ष जी। उनका ध्यान वहां पर होता ही नहीं था, उनका ध्यान केवल राजनीति चमकाने में होता था। लेकिन आज की ये जो सरकार है इस सरकार का ध्यान अध्यक्ष जी शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर आगे है और उसी के लिये आज ये सरकार उसपर काम करने का काम कर रही है अध्यक्ष जी। उसके साथ-साथ अध्यक्ष जी इस देश में एक नेता हैं जो अपनी सत्ता में आने के लिये पैदल चल रहे हैं, एक नेता हैं जो अपनी सत्ता बचाने के लिये रोड शो कर रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व है अध्यक्ष जी, एक नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिये, फिनलैंड जाने के लिये सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं हमें गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री पर, ऐसे नेता पर अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी आज पूरे देश ने ये देखा है कि किस प्रकार से अभी भाजपा के मित्र भी यहां बैठे थे जब भी कोई प्रश्न या Lt. Governor के बारे में

अध्यक्ष जी आता है वो ऐसे बिदक जाते हैं उनको जनता ने चुनकर भेजा है जनता की आवाज उठाने के लिये, जनता के काम कराने के लिये, लेकिन यहां बैठकर जो विपक्ष के साथी हैं, भाजपा के साथी हैं वो बैठकर वहां Lt. Governor के एजेंट बनके काम करते हैं, उनके वकील बनकर काम करते हैं, ये देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी और आज जैसे चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने का काम किया जा रहा है, लगातार दिल्ली के अंदर किस प्रकार से काम रोके गए अध्यक्ष जी, लगातार कैसे कामों में अड़ंगा Lt. Governor के द्वारा अड़ाया जा रहा है। संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बड़ी बात तो ये है कि आज तो Lt. Governor जो है वायसराय हो गए हैं। वो आज कहते हैं कि मैं तो संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं जनता की पीड़ा को नहीं समझता, मैं उसके दर्द को नहीं समझता, वो किसी को नहीं समझते, ये बहुत दुखद है अध्यक्ष जी, अगर लोकतंत्र की अंदर, अगर डेमोक्रेसी के अंदर ये देश जो है अध्यक्ष जी, ये देश जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा अध्यक्ष जी। ना की किसी और की मानसिकता से, ना की भाजपा के लोग बैठकर एक कमरे में डिसिजन कर लें ये देश उससे नहीं चलेगा अध्यक्ष जी, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कोई ना करे। अध्यक्ष जी, हम सब इसके लिये जो भी चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हों, चाहे उप-राज्यपाल साहब हो, सब इस संविधान से बंधे हुए है। ये एक ऐसी किताब है जिसका पालन हम सबको करना पड़ेगा। इसके नियम में रहकर हम सबको आगे काम करना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी, जो टीचर्स को फिनलैंड

जाने से रोकने की बात है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे टीचर्स फिनलैंड जाएंगे वहां से सिखकर आएंगे और वो हमारे बच्चों के ऊपर इम्पलीमेंट होगा, हमारे बच्चे गरीबों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और अच्छी होगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हम लोग मैं पिटिशन कमेटी में भी सौरभ भाई के साथ हूं हम पिटिशन कमेटी में देखते हैं अध्यक्ष जी, की हर अधिकारी, कोई ना कोई दबी जबान में आकर कह जाता है कि उप-राज्यपाल दिल्ली के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं, जो असंवैधानिक रूप से उसको रोकने का काम कर रहे हैं। आज अलोकतांत्रिक तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं और ये दिल्ली के लिये, देश के लिये बहुत दुखद है, इस डैमोक्रेसी के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार सर्वोत्तम है, चुनी हुई सरकार, चुने हुए विधायक, चुने हुए मंत्री और एक बात और दुखद है अध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विधायक, सभी मंत्री यहां से इकट्ठा होकर उप-राज्यपाल साहब के पास गए और दिल्ली के दो करोड़ लोगों के नुमाइंदे, जिनको एक ऐसी सरकार, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के सबसे लोकप्रिय मुंख्यमंत्री है।

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये कुलदीज जी।

श्री कुलदीप कुमारः सबसे सर्वश्रेठ मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर गए और लैटीनेंट गवर्नर ने दिल्ली के दो करोड़ लोगों का अपमान किया उनसे ना मिलकर। तो ये दुखद है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सौरभ भाई ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और लैफटीनेंट गवर्नर ने जो फिनलैंड टीचर को जाने से रोकने का काम किया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतना महत्वपूर्ण विषय जो Cooperative Federalism को भारत की सरकार स्वयं खत्म करने का प्रयास कर रही है। सरकारों के द्वारा जो विपक्ष की सरकारें हैं अलग-अलग राज्यों में वहां सदन में जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं और जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा चुने हुए राज्यपाल, उप-राज्यपाल उन सरकारों के सदन के द्वारा पास किये हुए प्रस्तावों को रोकने का और किल करने का काम कर रहे हैं, ये भारत के संघीय ढ़ांचे पर, ये भारत के Cooperative Federalism पर हमला है। आज पहले तो मैं अपने साथी सौरभ भारद्वाज जी के इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूं और इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और आज ही इस चर्चा के शुरू में मैं भारत में सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन के दो बड़े नेता देश ने अभी खोए हैं मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज ही के दिन रोहित वैमुला जिसको एक सांस्थानिक हत्या की गई उनका शहादत दिवस है, उनको भी मैं अपने श्रृद्धासुमन अर्पित करता हूं। गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले जी ने कहा था ज्ञान बिना मती गई, मती बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन के अभाव में भारत के 90 प्रसैंट से ज्यादा लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये सारा जो समस्या पैदा हुई केवल 90 प्रसैंट लोगों को वो ज्ञान का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिये हुआ। और मुझे दुख है कि आज उसी तरह की परिस्थिति, वो दिल्ली की सरकार जो भारत के अंदर एक मात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का

लगभग 25 प्रसैंट एजूकेशन पर खर्च करके युवाओं के भविष्य को तैयार करना, माताओं-पिताओं के बच्चों के सपनों को साकार करने का जो संकल्प हमारी दिल्ली की सरकार ने लिया और उस काम की शुरूआत की उस काम को जिस तरह रोका जा रहा है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक सुन्न हो जाता है, फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसीलिये अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। तो दिल्ली की सरकार तो लोगों को ज्ञानी बनाने की तरफ काम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार ने जितने भी विपक्ष की सरकारें देश में है, उन सबको पूरी तरीके से खत्म करने का एक संकल्प लिया है और Cooperative Federalism को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी वजह से जहां एक तरफ झारखंड की विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया उसको राज्यपाल ने लम्बे समय तक रोके रखा, जो छतीसगढ़ की सरकार ने पास किया उसको रोके रखा और दिल्ली की सरकार जो भी निर्णय ले रही है। उस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आ जाने के बावजूद जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी भी मुद्दे पर अगर असहमति रखते हैं या तो वो समर्थन दें और अगर असहमति रखते हैं तो वो किसी भी प्रस्ताव को रिजैक्ट नहीं कर सकते उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां टीचर्स को विदेश जाने से रोका ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दिल्ली की सरकार के सारे काम को रोकना चाहते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक्स के डाक्टर्स का स्टाफ की सेलेरी रोकी। उन्होंने दिल्ली के बाकी जो विभाग है उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्ट पर लोग

नौकरी कर रहे हैं या जो अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाहें कई-कई महीनों से रोक दी और लगातार हम देख रहे है एक प्रयास चल रहा है। वो प्रयास आज मुझे याद आ रहा है डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 25 नवम्बर, 1949 का भाषण जो उस वक्त की संविधान सभा के सामने उन्होंने इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि हम आज आजाद होने वाले हैं और अपने ही संविधान से शासन करेंगे। लेकिन भारत पहले भी अनेकों बार गुलाम हुआ। ये प्रजातंत्र भारत में कोई नया नहीं है। भारत में बुद्ध के समय में 15 गणराज्य थे जहां बाकायदा गुप्त मतदान से राजा चुना जाता था। लेकिन उसके बाद भारत अनेकों बार गुलाम हुआ और अब हम फिर आजाद हो रहे हैं। फिर से एक संविधान के द्वारा अपने देश का शासन चलाने वाले हैं। लेकिन क्या हमारी आजादी बरकरार रहेगी। इस मुद्दे पर संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए 25 नवम्बर, 1949 को डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दो बातों पर चिंता जाहिर की थी। एक तो बात ये थी कि जिस दिन देश के अंदर ऐसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जो धर्म को देश से ऊपर मानने लगे उस दिन प्रजातंत्र खतरें में चला जाएगा और दूसरी चिंता उन्होंने जाहिर की थी कि जिस दिन देश के लोग देश के किसी बड़े नेता के सामने इतने अंध भक्त हो जाएं कि अपने जीवन के सारे फैसलें लेने का अधिकार उसको सौंप दें। उस से तानाशाही बढ़ेगी और उससे एक ऐसा नेतृत्व पैदा होगा जो भारत में पेपर पर आजादी बचेगी लेकिन लोगों की आजादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज केन्द्र की सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को ना केवल परेशान कर रही है। सदन के अंदर जो फैसलें सरकारें ले रही है उन सरकारों को रोक रही है और राज्यपालों और उप-राज्यपालों के माध्यम से वो सरकार के काम को रोक रही है। मुख्य

मंत्री और उनके साथ पूरा मंत्री मंडल पूरे विधायक अपनी जनता की आवाज को लेकर अपने शिक्षा का मॉडल जो हमने पूरे दुनिया को दिल्ली से दिया उसके ऊपर जब हम बात करने जाते हैं तो एलजी महोदय मिलने से इन्कार कर रहे हैं। मतलब जनता के प्रतिनिधि से नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि ये भारत के प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक मोड आज साबित हो रहा है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत की इस आजादी को और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना और भारत के संविधान जिसके माध्यम से बाबा साहेब के बनाए संविधान से भारत चल रहा है। आज उस संविधान को भी खत्म करके, उस संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके ऐसा लगता है जैसे निर्णय सरकार खुद नहीं ले रही बल्कि लिखने का काम कोई और कर रहा है। चूंकि सरकार जो सत्ता में जिस पार्टी की सरकार है उसका तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में पूरे के पूरे सारे नेता उनके प्रधान मंत्री जी और सारे नेता चुनाव की ही तैयारी में रहते हैं। तो पढ़ते कब होगे। तो वो पढ़ते तो है नहीं, ज्ञान की तो बात करते नहीं है।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः मुझे इस बात का बेहद दुख है कि...

माननीय अध्यक्षः गौतम जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः मुझे इस बात का बेहद दुख है कि ये जो प्रजातंत्र के अंदर जो प्रजातान्त्रिक मूल्य हैं, जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करती है, नीतियां बनाती है। हम अगर आज टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं और एजूकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं। इसके साथ-साथ मुझे लगता

है इंजीनियर्स को डाक्टर्स को और भी जो फील्ड हैं उनके लोगों को भी बाहर भेजना चाहिए और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन उस काम को जिस तरह उप-राज्यपाल महोदय रोक रहे हैं इससे साफ प्रतीत होता है कि वो यहां केवल और केवल राजनीति करने के लिए आये हैं और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय की बात को नहीं मानते वो केवल राय है। संविधान की बात को नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को नहीं मानेंगे। आप कानून को नहीं मानेंगे। आप आखिर मानते क्या हो। क्या इस तरीके से तानाशाही चलाकर आप दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करके डायरेक्ट कन्ट्रोल करके डायरेक्ट सारे निर्णय अगर लेना शुरू करेंगे तो क्या प्रजातंत्र बचेगा। संविधान ने उप-राज्यपाल/राज्यपाल की व्यवस्था इसलिए नहीं की थी कि आप अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर दें। आप कोई भी बिल देख लीजिए कोई भी अप्वाइंटमेंट देख लीजिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट का वो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। अगर राष्ट्रपति जी ये कहना शुरू कर दें, इसमें तो राष्ट्रपति लिखा है तो मैं निर्णय लूंगा। तो क्या देश की चुनी हुई सरकार केन्द्र में जो सत्ता के अंदर है, मोदी जी के नेतृत्व में क्या वो काम कर पायेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान के मूल्य है बेसिक स्ट्रैक्चर है आप बेसिक स्ट्रैक्चर के खिलाफ जाकर देश की जनता की चुनी हुई सरकारों को आप उनके अधिकार को छीन कर उनको निस्तेनाबूद करने का काम कर रहे है। आप देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रहे है। आप देश के लिए खतरा साबित हो गए हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के लिए दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए हम लोग लडेंगे और ये जो आप बार-बार हर प्रस्ताव को रोक कर बैठ जाते हैं। हर चीज को जांच। अरे जांच किस

की करा रहे हो आप। हर चीज की जांच कराओगे। जहां जांच की जरूरत है, वहां जांच कराईये। लेकिन ये नहीं है जांच के नाम पर आप दिल्ली की सरकार के काम को रोक दो।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए। प्लीज।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः ये मैं बेहद दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय उप-राज्यपाल महोदय संविधान को एक बार अच्छे से पढ़िये और जो सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का जजमेंट है उसको ध्यान से पढ़िये। कानून से काम कीजिए आप। कानून से ऊपर नहीं है कोई भी व्यक्ति देश में। कानून से ऊपर नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय भीम।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमान दिलीप पाण्डेय जी।

श्री दिलीप पाण्डेयः बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एलजी साहब के मनोभाव को समझने की कोशिश कर रहा था। व्यवस्था को, तंत्र को, शासन को चलाने के जो तरीके हैं उसकी पृज़्ठ भूमि में जो हरकतें एलजी साहब कर रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शासन या तो राजशाही से चलता रहा है या लोक शाही से चलता रहा है। फिर मन में सवाल आया कि राजशाही से दिल्ली को चलाने का अगर मन्सूबा एलजी साहब का है तो वो तो राजा के पेट से जन्मे नहीं, फिर कैसे राजा वो दिल्ली के। फिर तो शायद लोकशाही किल होती हुई दिख रही है कारण कि जी एलजी साहब चुने हुए भी नहीं है। तो लोक शाही

से भी वो दिल्ली को नहीं चला सकते। संविधान का कितना मान सम्मान उनके दिल में है वो सौरभ भाई ने अभी बताया आज इस सदन के पटल पर। उन्हें किसी ने समझा दिया कि इन दोनों के अलावा तीसरा रास्ता है ना राजशाही चलेगी ना लोक शाही चलेगी, तानाशाही चलेगी। ये तीसरा रास्ता किसी ने समझाया उनको। नतीजा ये कि लोकतंत्र में से एलजी साहब ने तंत्र निकाल कर एलजी तंत्र बना लिया और सरेआम दिल्ली और देश के सामने एलजी तंत्र के जरिये तंत्र के जरिये लोगों का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। बेतुके सवाल पूछे जो रहे हैं। जिन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है। मकसद है उन सवालों को पूछकर काम को रोक देना। मैने उनके नोट्स पढ़े अध्यक्ष महोदय। एलजी साहब ने पूछा फिनलैंड क्यूं। कुछ भाजपा के नेता कन्फ्यूज हो गए। सौरभ भाई ने बताया वो फिनलैंड को थाईलैंड समझ बैठे थे। फिनलैंड क्यूं। थोडा पढ़ लिख लिये होते भाजपा के नेता और एलजी साहब तो पता चला जाता कि जो वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की Global Competitive Study है। अध्यक्ष महोदय, वो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाओं में शुमार करती है, फेहरिस्त में शामिल करती है, इस लिए फिनलैंड। फिनलैंड इस लिए कि प्री प्राईमरी से लेकर हायर एजूकेशन तक जो फ्री एजूकेशन एक्सेस है फिनिश लोगों को फिनलैंड के रहने वाले लोगों को, वो दुनिया के तमाम देशों में सबसे आला दर्जे की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, पूरे फिनलैंड के अंदर जो स्टूडेंटस की grading का मैकेनिज्म है वो बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा है। जहां हर शिक्षक को आजादी है अपनी क्लास के बच्चों को अपने तरीके से ग्रेड करने की। नतीजा की बच्चे मार्क पाने की दौड में शामिल ना होकर पढ़ने लिखने की सीखने की दौड में शामिल होते हैं। जानने की दौड में शामिल होते

हैं। लर्न करने पर उनका फोकस रहता है इस लिए फिनलैंड। फिर एलजी साहब ने पूछा कि ट्रेनिंग से क्या निकलेगा। cost benefit analysis (CBA) करिये आप, सीबीए करिए आप। मैं बहुत पहले अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हुआ करता था। तो पढ़ता था कि बड़ा अटपटा होता है। कुछ qualitative चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सीबीए नहीं करनी चाहिए। मसलन हम कहें और ये सवाल एलजी साहब के लिए है कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली की जो हमारी माएं हैं, बहने हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें आप। आपके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो अध्यक्ष महोदय, कोई पत्थर दिल ही होगा जो इस सवाल के ऊपर कहे कि नहीं पहले, पहले ये जो मकसद आपने बताया है इसकी cost benefit analysis करके बताईये आप। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये सवाल पूछना सीधे-सीधे आपकी insensitivity को दर्शाता है। आप महिलाओं की सुरक्षा जैसे मसले पर इतने असंवेदनशील हैं कि आप पूछने की, इसमें नफा नुकसान cost benefit analysis क्या होता है नफा नुकसान पता करके बताओ। इसमे फायदा क्या है वो बताओ आप। जिंदगी एक्सचेंज बिजनेस नहीं होती अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहता हूं समझना चाहता हूं। बच्चों का भविष्य करने में क्या नफा नुकसान देखता है कोई माँ बाप। हम अपने बच्चों को पढाते हैं कई। मतलब बच्चे सब कुछ हैं माँ बाप के लिए। पेट काटकर माँ बाप पढ़ाते हैं। मैं आज बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ हूं। आज आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूं क्योंकि पढ़ाया गया मुझे लिखाया गया। पेट काटकर माँ बाप ने पढ़ाया। कभी कोई माँ बाप नहीं सोचता कि आज बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूंगा इसकी जरा एक बार cost benefit analysis कर लेता हूं मैं। तब एडमिशन करूंगा अच्छे स्कूल में इसकी। कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता अध्यक्ष महोदय।

मुझे याद है 2021 नवम्बर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को घसीट कर चला रही थी तब निगम के स्कूलों के context में एक स्टेटमेंट आया था कि हम भी अपने निगम के टीचर्स को विदेश में भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए जिसका पूरा खर्चा जो है वो निगम उठायेगी। तब तो किसी ने नहीं पूछा cost benefit analysis के लिए। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र की सरकार के और राज्य की सरकारों के तमाम नेता, मंत्री और मुख्य मंत्री विदेश जाते हैं अध्यक्ष अध्ययन करने के नाम पर। क्या सीखकर आते हैं किसी ने नहीं पूछा। कौन सी cost benefit analysis किसी ने नहीं पूछा अध्यक्ष महोदय। जबकि 2017–18 के अदंर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक सिंगापुर गए थे अध्यक्ष महोदय। उस समय एक स्टेडी हुई। उन शिक्षकों को इन्क्लूड करके कि भई यहां से क्या लर्निंग लेकर आये शिक्षक। मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, वे शिक्षक जब लौटे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर तो वो वहां से flipped rooms का concept सीख कर आये। सिंगापुर से जो लैसन प्लानिंग होती है बच्चों की उसको कैसे रि–डेवलप किया जाए ये विधियां सीखकर आये वहां से। अध्यक्ष महोदय, go mad, go make a difference जो प्रोजेक्ट था, उसके कॉन्सेप्ट सीखकर आये। उसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इम्पलीमेंट किया अध्यक्ष महोदय। जब शिक्षक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सिंगापुर गए और वहां से लौटे तो कम्प्यूटर added learning labs को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में establish किया गया। ये अचीवमेंटस हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में हासिल किये हैं। नतीजा ये रहा कि दिल्ली के 18 लाख बच्चों का दिल्ली के नौनिहालों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो चला है। इसकी cost benefit

analysis करने को कह रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में दिल्ली के सरकारी स्कूल देश ही नहीं दुनिया के बेहतरीन सरकारी में है। जहां शानदार results आते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स के बच्चें आईआईटी क्वालीफाई करते हैं। बच्चे मैडिकल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। अमीर और गरीब को इस शिक्षा व्यवस्था ने बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया अध्यक्ष महोदय। मुझे गर्व होता है जब मैं दिल्ली के बाहर लोगों को बताता हूं कि दिल्ली के अंदर एक आईआईटी दिल्ली है जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ता है और हमारे यहां एक दर्जी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। वो सरकारी स्कूल से निकल कर पढ़ता है। सरकार ऐसी होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास किस्मत का दिया कम हो। जिसके पास भगवान का दिया कम हो। सरकार उसके लिए काम कर रही है। सरकार वो काम करने की कोशिश कर रही है लेकिन एलजी साहब रोक रहे हैं। अडंगा लटका रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं तो सदबुद्धि की प्रार्थना करूंगा कि परमपिता परमेश्वर एलजी साहब को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि अपने हुक्मरानों का आदेश तो एक तरफ वो दिल्ली के जो नौनिहाल हैं, जो उम्मीद से टकटकी लगाए आपकी ओर देख रहे हैं कि उनके शिक्षकों को आप फिनलैंड जाने देंगे। आप उन्हें जाने दें। मैं इस सदन के अंदर हमसे पहले जिन साथियों ने जो बातें रखी उससे सहमत होते हुए अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की साथी सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव रखा पूरा सदन उस प्रस्ताव के साथ है। मैं भी उस प्रस्ताव के साथ हूं। उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से जो एकमुस्त आवाज निकली है सदन के पटल से वो एलजी साहब के पत्थर दिल तक पहुंचेगी। उनके कानों तक पहुंचेगी। इस बात को समझेंगे कि रोडे

अटकाना, अडंगें लगाना ये किसी के हक में नहीं हैं, किसी के फायदे में नहीं है। लोकतंत्र को ऊपर रखिए। एलजी तंत्र को साईड में रखिए। संविधान का सम्मान करिये और दिल्ली सरकार को अपना सुर-लय-ताल लेकर काम करने दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद-धन्यवाद। अब माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय मुख्य मंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलने के लिए मैं इस सीट से कई बार पहले उठा। लेकिन आज बेहद दुख के साथ और बड़े भारी मन के साथ मैं अपनी बातें रख रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी सदन में मौजूद नहीं है। ये बेहद गम्भीर विषय है जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए। ये बेहद गम्भीर विषय है। इसके ऊपर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कई सारे मुद्दे पिछले दिनों में उठे हैं। इसके ऊपर मैं एलजी साहब के पास भी गया था मिलने के लिए तीन चार दिन पहले और मेरी जो बातचीत एलजी साहब हुई वो भी आज विस्तार से मैं इस सदन के सामने सभी एमएलऐज के सामने रखना चाहूंगा। मेरी इच्छा थी कि बीजेपी के साथी भी यहां मौजूद होते और वो भी बात सुनते ताकि इस चर्चा को एक कन्सट्रक्टिव रूप दिया जा सकता। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई है अब जिंदगी पूरे मेरी ही

सरकार रहेगी ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार पांच साल है दस साल है, पन्द्रह साल है, बीस साल है कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है। परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी-बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी है। केन्द्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केन्द्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों। और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा। उस टाइम जो भी सरकार होगी दिल्ली में। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते है। हम लोगों की इज्जत करते है। लोगों के मत की इज्जत करते हैं। लोगों के वोट की इज्जत करते हैं। जनतंत्र की इज्जत करते हैं। हम संविधान की इज्जत करते हैं। दिल्ली में दो करोड लोग रहते हैं। मैने हमेशा कहा है कि ये दो करोड लोग एक परिवार हैं। हमने हमेशा इसको एक परिवार माना है।...

इस परिवार में लोगों के जब भी कोई सुख-दुख होते हैं हम हमेशा सुख-दुख में काम आते हैं। इन 2 करोड़ लोगों के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनको हर्षिता और पुलकित से अलग नहीं समझता उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं तो जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है उतनी अच्छी शिक्षा मैं दिल्ली के एक-एक बच्चे को देना चाहता हूं ये मेरा मकसद है और उसी मकसद से हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो देश का भविष्य बनेगा बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने

शिक्षा पर इतना खर्चा भी किया इतने अच्छे-अच्छे शानदार स्कूल बनाए। जो सबसे ज्यादा आज स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल-निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। शायद 75 साल, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स का है और उनको मोटीवेट करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने उनको पूरी दुनियां में बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाई है। हमने बहुत सारे टीचर्स को विदेश भेजा, बहुत सारे टीचर्स को आईआईएमएस में भेजा बहुत सारे टीचर्स को अलग-अलग युनिवर्सिटीज में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हजार से ज्यादा टीचर्स, प्रिंसिपल्स को हम विदेशों में अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है। मैं मुख्यमंत्री हूं, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ने कह दिया भई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो बस ये फाइनल होना चाहिए यही तो जनतंत्र है और जनतंत्र क्या है। अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने भेजना चाहता हूं बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं दो बार आब्जेक्शन लगाकर फाइल के ऊपर भेजा अभी मैं पढ़कर सुनाउंगा थोड़ी देर में दो बार आब्जेक्शन लगाकर भेजा तो जब बार-बार आब्जेक्शन लगाया जाता है एलजी साहब कह रहे हैं न की मैंने तो मना थोड़ी किया। जब दो बार आब्जेक्शन लगाया तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ये आब्जेक्शन लगाएंगे तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है,

आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़े ही करता है वो आब्जेक्शन पर आब्जेक्शन आब्जेक्शन पर आब्जेक्शन फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो फाइल क्लीयर कर देगा। तो ये बार-बार जो आब्जेक्शन लगाये जा रहे हैं ये इसीलिए तो लगाये जा रहे हैं कि नीयत खराब है फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेकर आया हूं लिस्ट महोदय। बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं ये पूरी लिस्ट है जो खुद विदेशों में पढ़कर आए हैं। इनकी कभी इनके मां-बाप ने cost benefit analysis करी है। कितने ही एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़कर आए हैं। इनके कितने ही एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़कर आए हैं कभी इनके मां-बाप ने cost benefit analysis करी। ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीजेपी वालों के बच्चे जिन-जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई ऐतराज नहीं है मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में वो अपने बच्चों को भेजे जरूर भेजे अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा मैं इसके विरोध में हूं कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग। अगर हम अपने बच्चों को गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो तुम रोकने वाले कौन होते हो ये एक feudal mind set है। ये कई सौ साल पुरानी जो हमारे देश में feudal mind set है न की गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी

चाहिए गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए इसको तोड़ना है हम लोगों को और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए इस माइंडसेट को तोड़ना है, अपने को पूरे देश से तोड़ना है। आजादी मिल गई लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं पढ़ो एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, ये एलजी साहब की नोटिंग है इंडिया में करा लो। ट्रेनिंग अरे क्यों करा लें इंडिया में ट्रेनिंग, हम कम हैं किसी से, गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से। गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं हैं क्या, क्यों करा लें हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनियां में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है सबसे अच्छी ये सबको पता है फिनलैंड पूरी दुनियां में शिक्षा में नंबर वन है और उसमें भी जो नंबर वन युनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम पूरी दुनियां में जो नंबर वन युनिवर्सिटी हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का। टैक्स के पैसे से दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के देते हैं ये वो क्या कहते हैं 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना' XXX[1] अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ है। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गये हमारे देश को 75 साल हो गये हमारे देश को इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़

---

1 चिन्हित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे। इन लोगों ने जानबूझकर देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया और नंगे हो गये ये लोग। बड़े मजे की बात है एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की मैं अभी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है की भई तीन चीजें हैं एक है पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड इन तीनों चीजों को छोड़कर एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 04 जुलाई, 2018 को ये आर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है वो तो सबको माननी पड़ती है, है न। इसमें से मैं पढ़कर सुनाता हूं इसमें लिखा हुआ है पैरा-284 अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी जो तीन दिन से मैं बोल रहा हूं 284.17 पैरा इसमें लिखा है The Lt. Governor has not been entrusted with any independent decision making power इसकी हिन्दी क्या हुई Lt. Governor दिल्ली के Lt. Governor को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी उन्होंने दो बार लिखा। उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा There is no independent authority vested in Lt. Governor to take decisions अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ लिखा है भई एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी तीन दिन पहले तो मैंने ये पढ़कर सुनाया उनको मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कहते हैं हां सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ

कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं न ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेंप्ट है आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर इस देश के हर नागरिक के ऊपर बोले संविधान में लिखा है की एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके बाद मैं क्या कहता। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़े ही किया है मैंने कहा जी दो बार आपने वापस भेजी दी फाइल दो बार आपने लिखा, क्या लिखा पहली बार लिखते हैं मुझे यह बताया जाए की क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, ये जिस युनिवर्सिटी में भेज रहे हो इस युनिवर्सिटी ने और कौन-कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या आब्जेक्टिव हासिल होगा अरे मैं मुख्यमंत्री हूं मैंने देख लिया सारा। मैंने एलजी साहब को बोला मैंने कहा सर आप मेरे हैडमास्टर थोड़े ही हो। मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था फस्ट आया करता था क्लास में थ्रूआउट पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक फस्ट आया युनिवर्सिटी टापर था कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी में टाप किया था मैंने छठी पोजीशन थी मेरी, मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चैक नहीं किया जैसे ये एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा मेरे मास्टरों ने ऐसा नहीं किया जैसे ये एलजी साहब मेरा होमवर्क चैक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मेरे को चुनकर भेजा है आप कौन हैं, मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं।

ये मैंने पूछा एलजी साहब से मैंने कहा सर आप कौन हैं मेरे को तो जनता ने चुनकर भेजा कहते हैं मेरे को प्रेजीडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसराय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेजीडेंट ने पहले बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया आपकी सरकार में ये, मैंने कहा सर वो वाइसराय जो होते थे न वो कहते थे You bloody Indians, you do not know how to govern मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो You bloody Delhiwalas, you do not know how to govern मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो हमारे हालात पर हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। कहते हैं cost benefit analysis कराओ मैंने एलजी साहब से पूछा सर मेरे को वो धारा बता दो संविधान की मैं सारे ये सारे सर जो आज मैं ये लेकर आया हूं न ये सब लेकर गया था एलजी साहब के पास ये सारी चीजें लेकर गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी हैं अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको cost benefit analysis order करने की पावर किस कानून के तहत है। कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की cost benefit analysis मैं कराउंगा मेरे को जनता ने कहा है मैं cost benefit analysis कराउंगा। ये सदन है ये सदन कराएगा इसकी कमेटियां कराएंगी ये कमेटियां कराती हैं ये सौरभ मेरे को बताता है, राजेश बताता है, सोमनाथ ये सारे बताते हैं ये cost benefit analysis ये लोग कराएंगे आप कौन होते हो cost benefit analysis कराने वाले दिल्ली के अंदर चुनाव हार गये और उसके बाद अब cost benefit analysis आपके पास तो पावर नहीं है मैंने उनसे पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं था फिर मैंने उनसे पूछा मैंने कहा सर ये दस एल्डरमैन कैसे बना दिये आपने ये तो

आपके पास पावर नहीं है ये तो transferred subject है एमसीडी एक्ट तो transferred subject है आपने दस एल्डरमैन कैसे बना दिये बोल उस कानून में लिखा है administrator shall appoint 10 aldermen तो मैंने उनको ये एक और दूसरा आर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का। ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में इसमें लिखा है की जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी ये लिखा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ये तो राय है। उसके बाद एक हाईकोर्ट का आर्डर है वो भी मैं लेकर गया था और कुछ हो न हो एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। ये 1998 का जजमेंट है ओपी पाहवा इसमें साफ-साफ लिखा है मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन है Lt. Governor Govt. of Delhi means Lt. Governor इसमें लिखा है सारी पावर दिल्ली सरकार की होगी, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है Lt. Governor भी लिखा है तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है एलजी साहब की पावर नहीं है ये सारा मैंने उनको बताया पर वो तो माने ही नहीं वो तो बोले की मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। फिर मैंने कहा सर आप आजकल रोज चीफ सेक्रेटरी को आर्डर दे देते हो मतलब रोज सवेरे उठते हैं अपना लैटर हैड मंगाते हैं लैटर हैड में लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी इसको यहां का चेयरमैन बना दो और चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं चीफ सेक्रेटरी लागू करा देता है हम मुंह बाहकर देखते हैं, तो क्या हो गया ये टीवी में चल रहा है, अखबार में आ गया इसको लिख देते हैं ये इसको एल्डरमैन बना दो इसको यहां का ये

बना दो इसको ये चल क्या रहा है मैंने एलजी साहब से पूछा, मैंने कहा ये चीफ सेक्रेटरी को सीधे आर्डर कैसे देते हो? मुख्यमंत्री, मंत्री इनके थ्रू फाइलें क्यों नहीं जाती सीधे चीफ सेक्रेटरी को आर्डर दे देते हो आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बोले मैं शासक हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं कोई भी आर्डर दे सकता हूं किसी को भी आर्डर दे सकता हूं। न तो वो संविधान मानने को तैयार हैं और न वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मानने को तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा मैंने कहा सर ये योगा क्यों बंद करा दिया। मोहल्ला क्लीनिक के अंदर एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 तारीख को आये थे उसके दो महीने पहले से सारे डाक्टरों की तनख्वाह बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लीनिक के रेंट बंद करा दिये, सारी मोहल्ला क्लीनिक की बिजली बंद करा दी बिजली के बिल पेमेंट बंद करा दिये, सारे टेस्ट बंद करा दिये, मैंने कहा सर ये क्यों करा दिया। दिल्ली जलबोर्ड की तीन महीने से सारी पेमेंट बंद, बड़ी मजे की बात है कि 7 तारीख को नतीजे आए 8 तारीख को मोहल्ला क्लीनिक की सारी पेमेंट हो गई तो नीयत खराब थी। जलबोर्ड की सारी पेमेंट्स बंद करा दी हमारे जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। डीटीसी के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बस मार्शल हमने लगा रखे हैं उनकी तनख्वाह तीन महीने से बंद करा दी इन्होंने। मैंने सर बोला मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में ये कह रहे हैं की एलजी के आर्डर थे की या तो ये सारी पेमेंट बंद करो आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो नहीं तो तुमको, धमकी दी सारे अफसरों को की मैं सस्पेंड कर दूंगा, कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो।

जिन–जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी है उनको करो सस्पेंड आज तक सस्पेंड नहीं हुए। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी ये तो मेरे वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीटें आई हैं तो इसका मतलब जानबूझकर सारी पेमेंटें रुकवाई थीं ये बोले अब देखना तुम्हारी सात की सात सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहां पर लेफ्टीनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़े ही आये हैं दिल्ली को ठप्प करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं सर, हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीतें न जीतें राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं, देश जरूरी है, लोग जरूरी हैं, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके लोगों के मोहल्ला क्लीनिक बंद कराकर, लोगों के पानी बंद कराकर, लोगों की बिजली बंद कराकर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो चुनाव आपको मुबारक हम लोगों की सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी। हमारे लोगों ने इसलिए थोड़े लड़ी थी की एक वाइसराय जाएगा और एक लेफ्टीनेंट गवर्नर आकर बैठ जाएगा इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अध्यक्ष महोदय, अपने देश की आजादी को बरकरार हम तो सारे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं आजादी को बरकरार रखने के लिए

जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम सारे मिलकर वो कुर्बानी देंगे लेकिन जनतंत्र को और देश की आजादी को इस तरह से हम खराब बिलकुल नहीं होने देंगे। ये जो सौरभ का प्रस्ताव है मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वो न कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संकल्प स्वीकार हुआ

अब लंच ठीक सवा दो बजे हाउस दोबारा बैठेगा। लंच के लिए व्यवस्था है लंच करेंगे सभी सदस्य। धन्यवाद

सदन पुनः अपराह्न 2.30 पर पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुये।

माननीय अध्यक्षः हाउस की कार्यवाही शुरू करने से पहले एक सूचना देना चाह रहा हूं वैसे तो पहले एडवांस में सूचना गई है आज विधानसभा में पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्राति का शाम 6.00 बजे कार्यक्रम है। आदरणीय माननीय उप-मुख्यमंत्री जी भी आयेंगे, आप सब उसमें उपस्थित हों अपनी विधानसभा के साथियों को, मित्र मंडलियों को फोन करके बुला सकते हैं, धन्यवाद। सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागज़ात अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय

उप-मुख्यमंत्री कार्यसूची में दर्शाये गये अपने विभाग से संबधित दस्तावेज़ों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनीष सिसोदिया (माननीय उप-मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक-3 में दर्शाये गये दस्तावेज़ों की हिन्दी और अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

3.1. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2020-21 हेतु 7वां वार्षिक प्रतिवेदन (01/08/20 से 31/07/21 तक) (अंग्रेजी प्रति)[1]

2. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के वर्ष 2009-10 से 2017-18 हेतु वार्षिक लेखों पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित कृत्य कार्रवाई प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)[2]

3. इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 19वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां)[3]

4. प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 19वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां)[4]

5. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां)[5]

---

1 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23142 पर उपलब्ध।

2 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23143 पर उपलब्ध।

3 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23134 पर उपलब्ध।

4 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23132 पर उपलब्ध।

5 दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23133 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप-मुख्यमंत्री दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, (वर्ष 2023 का विधेयक संख्या-1) को सदन में introduce करने की परमीशन मांगेंगे।

श्री मनीष सिसोदिया (माननीय उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय में दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, (वर्ष 2023 का विधेयक संख्या-1) को introduce करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

श्री मनीष सिसोदिया (माननीय उप-मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो विधेयक है मूल रूप से जीएसटी कानून में जो स्टेट जीएसटी कानून है उसमें संशोधन से संबंधित हैं और जो जीएसटी कांउन्सिल है पूरे देश के सभी वित्त मंत्रियों की उसमें ये सारे संशोधन अनुमोदित किये जा चुके हैं अलग-अलग राज्यों में कई राज्यों में पारित हो चुके हैं कई में हो रहे हैं और सैन्ट्रल गर्वमेंट के एक्ट में भी ये सीजीएसटी में भी लागू हो चुके हैं तो दिल्ली के एसजीएसटी

में पूरे देश के कानून के साथ चलने के लिये अमेंडमेंट जरूरी हैं। ये लगभग–लगभग सारे अमेंडमेंट बहुत टैक्निकल नैचर के हैं बुक्स कीपिंग से लेकर एकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी और व्यापारियों की सुविधा के लिये टैक्स पेयर की सुविधा के लिये लाये गये हैं तो मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, वर्ष 2023 का विधेयक संख्या–1 को सदन में introduce करता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सही राम जी माननीय सदस्य तुगलकाबाद गांव के निवासियों को दिये गये demolition notice के संबंध में माननीय उप–मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कई दिन से ये संविधान की बातें हो रही हैं कि एल.जी. महोदय संविधान को नहीं मानते, केन्द्र सरकार तोड़–मरोड़कर अपने अनुसार उसका उपयोग कर रही है। इस संविधान ही नहीं अध्यक्ष महोदय मैं आज विधानसभा में सीधा–सीधा कहना चाहूं कि ये तो इतिहास ही बदलना चाहते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण मेरे हाथ में एक ये नोटिस है मैं चाहूंगा कि आपके पास भी भेजूं। कहने के लिये और देखने के लिये तो अध्यक्ष महोदय ये एक कागज का टूकड़ा है लेकिन इस कागज़ के टूकड़े ने कम से कम तुगलकाबाद गांव का जो इतिहास में नाम है उस इतिहास को ही खत्म करने का काम करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम 30 से 35 साल पुरानी वहां कॉलोनी बसी हुई है और अगर मैं तुगलकाबाद गांव की बात करूं तो तकरीबन आठ सौ साल पहले तुगलकाबाद गांव बसा हुआ है, 11 तारीख को ये नोटिस इश्यू हुये हैं भारत सरकार की तरफ से पुरातत्व विभाग से, अध्यक्ष महोदय इस कागज़ के टूकड़े ने 10 हज़ार परिवारों

की नींद तो हराम करी ही करी उनकी जिंदगी खराब करने का काम किया है। मैं सीधा-सीधा कहूं तो जो ये नोटिस है इसमें 15 दिन का टाइम उन गरीब लोगों को दिया गया है वो गरीब लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल से वहां बसे हुये हैं किसी ने अपने गांव की ज़मीन बेचकर दिल्ली में अपना घर बनाने का सपना देखा था, कितने ही लोग कबाड़ा बीन-बीनकर 30-30 गज के प्लॉट खरीद कर वहां 40 सालों से रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि जब ये कॉलोनी बसी उस समय पुरातत्व विभाग कहां गया था। आज की तो ये कॉलोनी बसी हुई नहीं है, 10 हज़ार मकान बने हैं आज वो कहते हैं जी कोर्ट के आदेश हैं। अध्यक्ष महोदय मैं कोर्ट से भी ये जानना चाहूंगा कि जब ये कॉलोनी कटी उस समय जो अधिकारी यहां ड्यूटी पर थे, या जो पुलिस अधिकारी वहां ड्यूटी पर थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही हुई आज तक? अध्यक्ष महोदय मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं है दिल्ली में इतनी कॉलोनी बसी हैं अलग-अलग क्षेत्रों में कि जो अधिकारी वहां होते हैं उनके खिलाफ भी कभी किसी ने केस किया हो किसी और सरकार ने तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले जो वहां के भाजपा के सांसद हैं साउथ दिल्ली के उन्होंने अपने घर पर उनके जो पर्यटन मंत्री हैं मेघवाल जी, उन्होंने अपने घर पर उनको इन्वाइट किया अपने घर पर बुलाया अब अध्यक्ष महोदय ऑन रिकार्ड बता रहा हूं मैं जबकि जब वो वहां से तीन बार विधायक रहे उनके संरक्षण में ये कॉलोनी पूरी काटी गई थी मैं पूरा-पूरा दावे के साथ आज विधानसभा में ये बात रख रहा हूं और 90 परसेंट कॉलोनी काटने में उन्हीं के परिवार का हाथ है और मैं तो सीधा-सीधा यहां कहूंगा इतना निकम्मा और बेशरम एम.पी. मैंने कभी नहीं देखा जो अपने ही गांव को

अपने ही कैबिनेट के मंत्री, पर्यटन मंत्री को बुलाकर अपने घर पर और ये आदेश दे कि इन सबको उठाकर यहां से बाहर कर दो, सबको तोड़-फोड़कर बाहर कर दो और यहां पार्क बनाने का काम करो। अध्यक्ष महोदय, 800 साल कम नहीं होते, 800 साल पुराना वो गांव है, इतिहास में उसका नाम है इतिहास के जब भी पन्ने पलटोगे इतिहास में उसका नाम मिलेगा लेकिन अब पता नहीं या तो एल.जी. महोदय के आदेश से दिल्ली को उजाड़ने की जो योजना है, कभी डीडीए के कहीं नोटिस मिलेंगे आपको जब से नगर निगम चुनाव खत्म हुआ है, कहीं आपको ऑर्कलॉजिकल के चुनाव, नोटिस मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को उजाड़ने का जो प्रोपोगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये दिल्ली के सब लोग जानते हैं अध्यक्ष महोदय, 20 हज़ार, 20 हज़ार तो वहां ऑन रिकार्ड वहां वोटर है जिन लोगों की वोटें बनी हुई हैं, पहचान-पत्र उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास है, राशन कार्ड उनके पास है अध्यक्ष महोदय मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से भी चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार को लिखें जो ऑर्कलॉजिकल का इनका पर्यटन मंत्री है मेघवाल जी उसको भी आप लिखें कम से कम ऐसी कड़कती सर्दी में अगर इन पर बुलडोज़र चलाते हो गरीब लोग कहां पर जायेंगे अध्यक्ष महोदय। अभी बच्चों के बोर्ड मगंउ भी होने जा रहे हैं आज आलम ये है कि जो बच्चे मगंउ देने जायेंगे अब उनकी हालत ये है कि वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं वो आगे आने वाले समय में क्या मगंउदेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया है उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 15 दिनों के बाद तुम घर से बेघर हो जाओगे, अध्यक्ष महोदय इतनी बड़ी आबादी

को घर से बेघर करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वो केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्री को लिखें अगर इनको हटाना ही है किसी कोर्ट के आदेश भी हैं तो पहले कहीं इन्हें बसाने की योजना तैयार करें क्योंकि अभी कई जगह मैंने देखा है कि हाई कोर्ट में भी आदेश हुये हैं, सूप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किये हैं कि अगर आप किसी को कहीं से हटाने जा रहे हो तो उससे पहले उसे बसाने की योजना तैयार की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय मैं कहूं सीधे-सीधे कि इसमें जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे क्योंकि 8 साल से में वहां विधायक हूं मैंने दिल्ली जल बोर्ड के बोर करने की वहां कोशिश की लेकिन तुरंत ऑर्कलॉजिकल के आदमी आ जाते हैं पुरातत्व विभाग के दिल्ली पुलिस के जवानों को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑर्कलॉजिकल की ज़मीन है यहां आप बोर नहीं कर सकते। वहां रोड़ बनाने की कोशिश की, ठेकेदार की ये और उठाकर बंद कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय कई सालों से वहां बिजली के मीटर कनैक्शन नहीं दिये जा रहे, अध्यक्ष महोदय जब हम वहां सरकारी डिपार्टमेंट से काम नहीं करा पाते तो इन लोगों ने सरकारी ज़मीन को किस-किस ने काटा उन colonizer के खिलाफ एफआईआर हो और उनकी जांच हो उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये क्योंकि उनकी लापरवाही से उनकी गलती से आज 10 हज़ार परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। अध्यक्ष महोदय, जब-जब चुनाव आते हैं तब-तब ये भारत गिराव पार्टी है जो इनका एक ही नारा होता है कि हम आपकी अनॉथराइज़ कॉलोनी को पास करेंगे दूसरा नारा होता है कि जहां झुग्गी वहीं मकान अभी आपने देखा होगा निगम चुनाव में हर झुग्गी-झोंपड़ी के बाहर होर्डिंग लगे हुये थे मोदी जी के कि आप भारतीय

जनता पार्टी को वोट दो जहां आपकी झुग्गी है, वहीं आपको मकान बनाकर दिया जाएगा। मैं अपने विधान सभा की बात करूं, आतिशी जी की विधान सभा में वो फ्लैट बने हुए हैं। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो अपने किराये की बस करके मेरी विधान सभा से लोगों को ले जाकर दिखा रहे थे कि ये देखो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मोदी जी आपको यहां यह फ्लैट देंगे।

अध्यक्ष महोदय, उन फ्लैटों की तो बात छोड़ो, आदेश कि खाली इस नोटिस के माध्यम से और ये समय ये चर्चा और है कि अगर 15 दिन में आपने अपने मकान को तोड़ कर वहां से नहीं हटाया तो जो बुलडोजर आएगा, जो फोर्स आएगी, उसका पैसा भी आपही से लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों की देख-रेख में ये कॉलोनी काटी गयी, सबसे पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर हो और जिन लोगों ने इन गरीब लोगों से पैसे वसूले, उनके खिलाफ भी एफआईआर होके उनसे पैसे वसूल करके, केन्द्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को बसाने का काम करो उजाड़ने से पहले इनको बसाने का काम करे।

अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने देखा था जब सुबह विधान सभा शुरू हुई तो काली पगड़ी पहनकर लोग आए थे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि काली पगड़ी पहनने वालों तुम्हारा दिल भी काला है और अगर एल.जी. महोदय ने, केन्द्र सरकार ने तुगलकाबाद के गांव के लोगों को या कहीं झुग्गी-झोपड़ी के लोगों को उजाड़ने का काम किया तो 2024 में काली पगड़ी वाले तुम्हारे दिल भी

काले हैं। अगर आप लोगों ने इस तोड़ फोड़ को नहीं रोका तो 2024 में तुम्हारा दिल्ली की जनता तुम्हारा मुंह भी काला करके देगी, आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं और एक बार पुनः आपसे भी अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय कि आप भी पर्यटन मंत्री को लिखके कि इन गरीब लोगों को न उजाड़ा जाए क्योंकि इन्होंने तो पैसे देकर खरीदी है जमीन, फ्री में नहीं ली। जब इन्होंने ये खरीदी थी उसी समय इनको रोकना था। उस समय दिल्ली पुलिस कहां गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, एक फिल्म में डायलॉग है कि अगर पुलिस ठीक हो न तो मंदिर के बाहर एक जोड़ी चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता, तो इसमें तो मैं कहूंगा जितने भी अधिकारी इसमें शामिल है, उनकी जांच हो, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। आपने इतने गंभीर मामले पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये जो विषय है जो आपके सामने होगा। आपने पढ़ा होगा। शायद टी.वी. में भी देखा होगा और प्राइम टाईम पर भी चला था। मैं इसके ऊपर जो बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी मेरे सदन में बैठे हैं, वो जरा तसव्वूर करें जो मैं बात बता रहा हूं तो उसको देखें उसको visualize करें कि वो क्या चीज है। 2013 के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ और 2014 के अंदर आप सब समझिए की जैसे एक दिल्ली के अंदर एक नायक आए जैसे एक पिक्चरों के अंदर एक हीरो होता है। उस हीरो ने छोटी पिक्चर में तो दिखा देते हैं, छोटी सी बस्ती को बदल दिया। लेकिन,

उस हीरो के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था तो उसने अपने कुछ साथियों को अपने छोटे भाईयों को उन क्षेत्रों में भेजा और कहा कि देखो जनता के क्या क्या दर्द हैं। बहुत सारे तो उन्हें पता थे, लेकिन और वो जानना चाहते थे कि पार्टिकुलर छोटे-छोटे एरिया में क्या और तकलीफें हो सकती हैं।

ऐसे ही एक उनका छोटा भाई एक क्षेत्र में गया और देखा कि लोगों में क्या दिक्कतें हो सकते हैं। शिक्षा की दिक्कत थी, स्कूल बहुत अच्छे नहीं थे। चिकित्सा की दिक्कत थी, हॉस्पिटल्स मोहल्ला क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक तो थे ही नहीं तो पॉलिक्लीनिक्स थे वो अच्छे नहीं थे। सुरक्षा की दिक्कतें थी, कहीं कोई कैमरे वगैरह तो बहुत दूर की बात है। कोई देखने वाला नहीं था और एक बहुत बड़ी दिक्कत थी प्रतिष्ठा की। जहां पर लोगों को इस तरीके के जिंदगी जीने के लिए मजबूर करा जाता था कि उनको लगने लगे कि वो एक कीड़ें-मकोड़े है। उनकी कोई इज्जत, मान, सम्मान है ही नहीं। वो देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे हर चीज के लिए तड़पना पड़े। रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए कहा जाता है कि सबसे जरूरी चीज होती है एक आदमी की। उसी के तरीके से एक चीज होती है इज्जत। एक जानवर और इंसान के अंदर एक फर्क होता है। जानवरी को भी खाना चाहिए, सिर छुपाने के लिए गुफा चाहिए, ज्यादा ठंड होती है तो कुत्ता गाड़ी के नीचे घूस जाता है। लेकिन इज्जत के लिए इंसान मरता है और वो इज्जत तार तार हो जाती थी। जब ये देखा कि वो औरतें, वो बच्चियां अपने घर से निकलती है और एक खुले मैदान के अंदर शौच करने जाती हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आप दोबारा से जरा इसे तसव्वूर कीजिए एक 15 साल की लड़की रात को 11.00 बजे उसको शौच आता है, उसे खुले में जाना है। अब

वे अकेले नहीं जा सकती। इस सदन में मेरी कुछ बहनें बैठी हैं। अकेले नहीं जा सकती। उसी झुग्गी के अंदर उसके मां, बाप रहते हैं, वो उन्हें भी नहीं उठा पाती क्योंकि उसका बाप दिन में काम करके आया, उसकी मां किसी के वर्तन धो कर आयी है। वो अपने पड़ोस में किसी को उठाती है। दो तीन सहेलियां इकट्ठे होती है, तब तक वे वेट कर रही है तब तक वो आएंगी। उन्हें लेके उस खुले मैदान में जाती हैं। साथ में एक टोर्च चाहिए क्योंकि अंधेरा है। इतनी लाइट भी नहीं हो सकती, ज्यादा लाइट होगी तो भी दिक्कत होगी क्योंकि उसे ऐसा काम करना है जो कि छुपके करना है। तीन लड़कियां जाती हैं, एक ग्रुप जाता है। इधर-उधर देखती है कि बेचारी कोई विडियो न बना ले। अब वो छुपके काम करती है, जिसे दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता, कोई जानवर रोक नहीं सकता? एक बेसिक चीज हैं आदमी की। एक मकान में अगर बेडरूम न हो आप जमीन पर सो सकते हैं। रसोई न हों तो आप कमरें में खाना बना सकते हैं, लेकिन शौचालय न हों, आप तसव्वूर कीजिए सर दो मिनट भी वेट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे ये जरूरी चीज बताई गयी कि अगर कभी या हमारी सरकार बने, उस नायक का वो छोटा भाई जो वहां से देखके गया उसने बताया कि सबसे जरूरी हो तो ये शौचालय बनाये जाएं इन सबके लिए। 2015 में सरकार बनी। 13 में तो क्योंकि बहुत कम समय के बनी। 15 में वो सरकार बनी जो सबसे पहला काम किया गया, उन झुग्गी वालों के लिए वो शौचालय बनाये गये। बड़े बड़े बॉक्स बनाये गये, उनमें लाईट की व्यवस्था की गयी, उनमें पानी की व्यवस्था की गयी ताकि घर से डब्बा न लाना पड़े ताकि घर से टोर्च न लानी पड़े। वो लड़की अकेली भी जा सके क्योंकि उस लड़की के लिए बहुत अच्छे स्कूल भी बनाये थे उस हीरो ने। उस स्कूल के

अंदर तो वो साफ शौचालय में जा रही थी। जब घर आयी तो खुले में कैसे जाती तो उसने कहा हां यहां भी मेरे लिए एक शौचालय बनायें, मैं अकेले भी जा सकती हूं। चार-पांच साल से वो शौचालय बहुत अच्छे चल रहे थे। 16 में 17 में बनकर खड़े हो गए थे।

गत 5 तारीख को वहां पर पांच हजार फोर्स लगायी गयी। मैंने अपने जीवन में इतनी सीआरपीएफ कभी नहीं देखी। इतने सारे आंदोलन कर लिए पार्टी के साथ में, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, पुलिस भी थी। लोग शोर मचा रहे थे, उनको आने नहीं दिया गया। 50 जेसीबी खड़ी की गयी। पहली बार देखा कि शौचालय को तोड़ने के लिए ऐसी सैना आयी जैसे कि कोई पाकिस्तान ने इस देश ऊपर आक्रमण किया हो। जहां पत्थर लगे हुए थे कि माननीय केजरीवाल जी ने इन शौचालय को बनाया, मेरा नाम उसमें लिखा था। उसपे आकर बुलडोजर को मारा गया क्योंकि शायद तकलीफ इस बात से थी कि यही वो लोग है, जो लगातार आम आदमी पार्टी को जिताते हैं।

मैं अगर आपको वो विडियो दिखाऊं, किस तरीके से जब मैं वहां प्रदर्शन कर रहा था पुलिस ने वो हमें ले गये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है। उन्होंने वहां गाड़ियां लगाई हैं और हम सब जानते हैं न वो गाड़ियां कभी साफ हो सकती हैं न उन्हें कोई लाईट की व्यवस्था है और वही खौफ जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। वही तीन, चार लड़कियां इकट्ठी होकर जाएंगी। अगर किसी का पेट खराब हो, तबियत खराब हो आप समझ सकते हो उसकी क्या हालत होती। इसलिए कहते हैं माननीय एलजी साहब चाहते हैं कि वहां एक गार्डन बनाया जाए। बड़े बड़े

होर्डिंग्स भाजपा के लोगों ने वहां लगाया। बैष्णवी गार्डन बनाएंगे। शायद स्टार्टप शुरू करना चाहते हैं वहां पर। गार्डन में खाद की जरूरत होती है। ताजा खाद मिलेगी उनको वहां। अरे कोई ऐसी चीज तो है नहीं क्या आप रोक दोगे, शौचालय तोड़ दोगे तो लोग जाएंगे नहीं। लोग तो जाएंगे, अब उस गार्डन में जाएंगे। उस खूबसुरत गार्डन में जाएंगे, खाद देंगे उनको, स्टार्टप होगा, एक नया पी में स्टार्टप शुरू हो गया।

देश में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया। लूट कर ले गए। बहुत सारे आए मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, महमूद गजनवी आया। बाबर आया तो हिन्दुस्तान में रूक गया, अंग्रेज आए तो रूके भी नहीं और लूटते भी रहे। उनमें और आज की सरकारों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि सरकार को हम चुनते हैं। जब जनता चुनती है तो कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ सपनों के साथ चुनती है। जो पार्ज़द, जो विधायक, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको ये मालूम होता है कि मेरी जनता का दर्द क्या है।

अरे बनाना तो दूर आप उसे तोड़ रहे हो, एक पार्क के लिए। आपको इतनी भी दर्द भी नहीं आई और शर्म भी नहीं आई। आप बहुत काम करना चाहते हो न, आप एक बार भी आकर उन झुग्गियों में घूमते, जो शौचालय आपने तुड़वाए। आप आइये। मैं माननीय एल.जी. साहब को न्यौता देता हूं वो मेरे साथ चले। वहां घूमे, लोगों से पूछे क्या चाहते हैं। और मजेदार बात बताता हूं, उसके साामने कुछ कोठियां हैं और एक तरफ फ्लैट्स हैं, मैं उनको उसमें लेकर चलूंगा। सर, उन कोठी वालों के घरों में बदबू आती है, वो शौचालय बन गए थे, वो बदबू बंद हो गई थी। उन फ्लैट्स वालों के घर में वो बदबू बंद हो गई थी। तो आपने 'स्वच्छ भारत अभियान' का अच्छा मजाक उड़ाया।

वो कोठी वाले भी दुखी हैं और फ्लैट्स वाले भी दुखी हैं। इतना बड़ा महापाप, क्या बिगाड़ा था उन बच्चियों ने आपका? कितनी मुश्किल से कुछ लोगों को आदत पड़ी थी। ये आदत पड़ जाती है खुले में जाने की। आपने उनकी इज्जत को, मान-सम्मान को तार-तार करना था। आपने उनको डराना था।

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड करिए राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ताः आपने उनको ये बताना था कि दिल्ली के अंदर...

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए।

श्री राजेश गुप्ताः एक ऐसी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको रोकना है और ऐसे नहीं तो वैसे सही। मेरा ये कहना है कि जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, अगर उनको ये लगता है कि ऐसा करने से वो दिल्ली जीत लेंगे, लोक सभा जीत लेंगे, पहली बात तो ऐसा जीतना जीतना नहीं है, सिकंदर भी खाली हाथ गया था दुनिया से, कुछ नहीं लेकर गया। बद्दुआएं ले रहे हैं वो।

और दूसरी बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहां नहीं हैं लेकिन ये सारे विधायक बैठे हैं उनके, दिल्ली जीतना तो बहुत दूर की बात है साहब, जो 8 ये बैठे थे न सुबह, ये भी वापस हम जीतेंगे, हम आपको दिखायेंगे, ये भी वापस आयेंगी क्योंकि दिल्ली की जनता के जो आंसू निकले हैं, जो लड़कियां वहां रोती हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा सेशन बुलाए जिसमें मैं वो विडियों सारी चलाऊं यहां पर, आप देखिए वो बच्चियां क्या कह रही हैं और वो एल. जी. साहब तक पहुंचे और ओपन में एक सेशन हो, जो लोग देखे, जनता देखे, मीडिया आए और उनके कानों तक एक बात जाए, प्रधानमंत्री जी को भेजे

आप वो विडियों कि 'स्वच्छ भारत अभियान' ये है आपका। लोक सभा के स्पीकर को भेजे आप।

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब कंक्लूड करिए ये।

श्री राजेश गुप्ता: सुप्रीम कोर्ट में भेजे आप कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र का ये मजाक बनाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: राजेश जी, अब कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड करिए।

श्री राजेश गुप्ता: मेरी आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, आप इस बात का संज्ञान लें और हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी-बड़ी संस्थाए हैं, जो प्रजातंत्र के pillars हैं, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, लोक सभा, जहां भी आप भेज सकते हैं, इसे भेजें और जो मखौल एल.जी. साहब ने दिल्ली की जनता का उड़ाया है, वो सबके सामने आए। आपके बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव: आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, महरौली विधान सभा के साथ भी अन्याय हो रहा है। 12 दिसंबर को एक डीडीए का नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर, लगभग 3 से 4 हजार मकानों को 10 दिन के अंदर आप इसको हटा लीजिए अन्यथा ये सारा का सारा डेमोलिश कर लिया जाएगा और उसकी कॉस्ट भी आपसे ली जाएगी। लगभग इसमें अध्यक्ष जी 1 हजार के करीबन झुग्गियां हैं, 3 से 4 हजार पक्के

मकान हैं, मल्टी-स्टोरिज हैं और ये सारे मकान और झुग्गियां जो बनी हुई है अध्यक्ष जी लगभग 30-40 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये सारा का सारा हो रहा है आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर। अध्यक्ष जी, डीडीए ने डिमार्केशन करके एक बाउंडरी वॉल बना दी गई कि इस बाउंडरी वॉल्स के अंदर-अंदर आप लोग रह सकते हैं, उससे बाहर का सारा एरिया आर्कियोलॉजिकल पार्क का है। लेकिन उसके बावजूद भी, जो ये मैं चर्चा कर रहा हूं ये उस बाउंडरी से अंदर का एरिया है जहां लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं और जहां बकायदा रजिस्ट्री होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी फीस लेता है, सरकारी फीस ली जाती है और उसके बावजूद भी इस तरह का नोटिस दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इसमें बहुत बड़ा एरिया महरौली का आता है। इसमें सेंट जॉन स्कूल का एरिया आता है, महरौली बस स्टैंड है हमारा, चर्च कॉलोनी कंपाउंड है, गुरूद्वारा सिंह साहिब एरिया है, हनुमान मंदिर एरिया है, जमीला मस्जिद है, कदीमी दरगाह, निरंकारी भवन के आसपास का एरिया, कुतुबग्रीन अपार्टमेंट है, तनिज़्क अपार्टमेंट है, जैन मंदिर है, बहुत पुश्तैनी, बहुत पुराना जैन मंदिर है, ऐतिहासिक जैन मंदिर है, उसके साथ आसपास का एरिया है वार्ड नंबर 8 में, लाल बिल्डिंग का एरिया है, विश्वकर्मा मंदिर के आसपास का एरिया है, मुल्तान धर्मशाला बनी हुई है। Maruti Competentds आसपास की मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। शमशान घाट अंधेरिया मोड़ के आसपास का एरिया है और येगौसिया कालोनी है। अध्यक्ष जी, ये वो एरिया है जिसके कुछ केसिस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और लगभग इस नोटिस के अंदर भी जो लगभग इन्होंने सारे खसरा नंबर्स दिए हैं, उसमें से 163 खसरा नंबर, 166, 217, 214, 15, 16, ये सारे खसरा नंबर्स पर कोर्ट की स्टे है। अध्यक्ष जी,

अलग-अलग कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं जो मैं आज यहां लेकर आया हूं आपके संज्ञान में लाने के लिए। ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं इस एरिया में भी ये डेमोलिशन का नोटिस चिपकाया गया है। पूरे इलाके के अंदर इस नोटिस को चिपका दिया गया, वहां ये नहीं देखा गया कि ये एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। अध्यक्ष जी, ये हुआ है जो एमसीडी के चुनाव होने के बाद, तो इसका मतलब बीजेपी की मंशा बिल्कुल क्लीयर है और लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग, प्रोटेस्ट भी हुआ है, आगे भी प्रोटेस्ट होगा। जहां 30 से 40 हजार लोगों का ये मामला हो तो लोग तो सड़कों पर भी आयेंगे और अपने हक की लड़ाई लडेंगे। तो अध्यक्ष जी ये बिल्कुल गलत एक नोटिस दिया गया है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें कुछ एरिया डूसिब में आ रहा है और बकायदा डूसिब में जो कॉलोनी का नंबर दिया जाता है उसमें 769 नंबर है डूसिब में, और उसके अंदर भी, डूसिब के अंदर भी काफी झुग्गियों का जिक्र किया गया है जबकि वहां पर हकीकत में हजार झुग्गियों से ज्यादा झुग्गियां हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी इसके कुछ केसिस इंटेक के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं जोकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत वो लैंड आती है, उस लैंड पर भी यहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं जबकि जो ऑर्डर्स हैं उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को और जो भी ऑथराइज occupants है उसको किसी भी तरह से वहां से न हटाया जाए, ये आदेश कोर्ट के आए हुए है पहले से। लेकिन डीडीए और एल.जी. साहब के आदेश से इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया है और किसी तरह की किसी स्टे पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी मेहनत की कमाई से वो फ्लैट्स

खरीदे हैं और ऐसे–ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे–ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिदंगी की कमाई वहां लगाई थी और आज उनका बहुत बुरा हाल है और दहशत में जी रहे हैं। ऐसा न हो कि कुछ लोग तो इस दहशत से हार्ट अटैक से ही मर जाए। अध्यक्ष जी, बहुत बुरी सिचुएशन में आज महरौली के लोग हैं और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं जो आर्कियोलॉजिकल पार्क डेवलपमेंट के नाम पर ये नोटिस दिया गया है, वो एरिया मार्क्ड है, बकायदा उसमें दीवार कर दी गई है और वो सफिशिएंट एरिया है और वो एक समय डिमार्केशन करने के बाद किया गया है, तभी डीडीए ने वो दीवार की थी। उस दीवार का जिक्र भी एक हाई कोर्ट के ऑर्डर में किया गया है कि वो वहां दीवार बना दी जाए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए अगर, जितना भी उनका एरिया है उस पर अपनी दीवार कर दें ताकि उससे आगे अगर कोई बढ़ेगा तो उसको डेमोलिश किया जाए। लेकिन किसी तरह का कोई भी लोगों को ये न्याय नहीं मिल रहा है और डीडीए वाले रोजाना ये आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर, जी–20 के नाम पर, इस तरह की ये कार्रवाई करने लग रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि ये नोटिस वापिस लिया जाए, ये बिल्कुल गलत नोटिस है और एल.जी. साहब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से दिल्ली की जनता को ये लोगों केखिलाफ काम न करें। दिल्ली सरकार के खिलाफ तो आप काम कर ही रहे हैं, दिल्ली सरकार को तो आप काम नहीं करने दे रहे हैं लेकिन अगर दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली के खिलाफ आप इस तरह के नोटिसिस जारी करेंगे, क्योंकि छतरपुर में भी काफी ऐसे नोटिस इशू किए गए हैं। सही राम जी ने भी अभी अपनी बात रखी है। इसके अलावा अजय दत्त जी के यहां पर भी है। बहुत सारे हमारे जो विधान सभा क्षेत्र, हमारे

विधायक हैं उनके यहां भी, राजेश जी ने भी अपनी बात रखी, उनके भी टॉयलेट्स को गिरा दिया गया जो डूसिब के थ्रू बनाए गए जबकि टॉयलेट का तो कोई ऐसा कब्जा नहीं माना जाता। टॉयलेट तो आज मैन रोड्स पर बनाए जाते हैं, लोग चलते हुए, पीडब्लूडी रोड पर बनते हैं, दूसरी लैंड्स पर बनते हैं। तो इस तरह की अराजकता आज डीडीए द्वारा एल.जी. के थ्रू की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं इस सदन से कि ये नोटिस वापिस होना चाहिए महरौली वाला और जितने भी लोग यहां पर अपना मकान, अपनी मेहनत से मकान जो खरीदे हैं उनके आशियाने बचने चाहिए और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री नरेश यादवः जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई जगह झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का काम चल रहा है और ये बहुत दुखद है क्योंकि बहुत समय से दिल्ली में लोगों ने अपने छोटे-छोटे आशियाने बनाए और जिनकी वजह से दिल्ली पूरी चल रही है। मेरी विधान सभा, अंबेडकर नगर में खानपुर वार्ड में एक नया ही तरीके से झुग्गी तोड़ने का काम शुरू हुआ है। एमबी रोड, खानपुर जिसमें आता है यहां पर मेट्रो एक नई लाईन बिछाने का कार्य कर रही है और कुछ समय पहले मेट्रो जमीन एक्वायर कर रही थी और उस जमीन

में बहुत सारे मकान आए और कुछ झुग्गियां आई तो मेट्रो ने पहले आदेश दिया कि हम सब मकानों को लेंगे, उनका मुआवजा देंगे और जो झुग्गी हैं उनको भी जहां पर हमें रिहैबिलिटेट करना है उनको रिहैबिलिटेट किया जायेगा कुछ झुग्गी वालों ने अपने भरण पोषण के लिये छोटे छोटे इसमें किसी ने छोटी सी दुकान लगा ली, किसी ने रेहड़ी लगा ली, किसी ने अपना कुछ लगा के अपना भरण–पोषण भी वो वहीं से कर रहे हैं। तो मेट्रो ने आश्वासन दिया था ये लिखित में है कि हम इन झुग्गी वालों को भी रिहैबिलिटेट करेंगे और इनको झुग्गी देंगे या इनको दुकान बना के देंगे। तो ये सब चुनाव से पहले की प्रक्रिया थी चुनाव के बाद सडनली झुग्गी वालों को नोटिस आता है कि ये जमीन ड्यूसिब को दे दी गयी है और ड्यूसिब से यकायक एक नोटिस सब झुग्गियों पे लग जाता है कि ये तोड़ी जायेंगी और इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। मैंने इसके बारे में पूर्व में जो सीईओ थे के. महेश जी उनसे बात करने की कोशिश की, वो किसी कारणवश इसपे एक्शन नहीं ले पाये और इसी बीच क्योंकि ये काम जल्दी होना था झुग्गियों को रोकना था तो झुग्गी वाले सब मिल कर कोर्ट गये और कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये अभी स्टे कर रहे हैं इसको हम तफशीश से देखेंगे। तो अभी उन झुग्गियों पे स्टे लगा हुआ है। उसके बाद मैं अभी जो ड्यूसिब की सीईओ हैं गरिमा गुप्ता जी उनसे मिला, उनके सारे स्टाफ से बात हुई और अब ये निकल के आ रहा है कि ड्यूसिब शायद इसपे कुछ काम करे। लेकिन इसमें एक अजीब सा पेंच मेट्रो की सर्वे टीम ने फंसा दिया है कि क्योंकि यहां पर झुग्गी वाले कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करते थे अपना भरण पोषण के लिये उन्होंने कोई रेहड़ी लगा रखी थी या कोई चाय की दुकान खोल रखी थी तो ये कमर्शियलाईज प्लेस है जबकि झुग्गी में कमर्शियलाईज प्लेस

हो ही नहीं सकता और इसी तथ्य को लेके ड्यूसिब के लोग कह रहे हैं कि जी ये कमर्शियलाईज है ड्यूसिब कह रहा है कि हमारी कुछ पालिसियां भी इसमें क्लियर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से पहले तो मेट्रो से ये कहना चाहता हूं कि जब आपने लिखित में ये दिया है कि इन झुग्गियों को तोड़ने से पहले आप झुग्गीवासियों को रिहैबिलिटेट किया जायेगा तो ये हो। और दूसरा कि अगर ये ड्यूसिब के पास जाये तो वो दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार उनको पहले रिहैबिलिटेट करे उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो क्योंकि ये लोग ये झुग्गियां मेरे जन्म से पहले की वहां बसी हुई हैं। और इतनी बड़ी तादात में अगर हम झुग्गीवासियों को तोड़ेगे तो मुझे ये लगता है कि ये मेट्रो ने वहां से ट्रांस्फर करके क्यूं किया, कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है जहां भी पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे देश में मेट्रो अगर अपनी लाईन डालती है तो वो चाहे झुग्गी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो उनको रिहैबिलिटेशन करने की जिम्मेदारी मेट्रो की है। तो मैं आपके माध्यम से मेट्रो को ये संदेश देना चाहता हूं मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी उनको आदेश दें कि इन झुग्गियों को मेट्रो पहले वहां से उनके लिये जगह दे, जमीन दे, या दुकानें दे या मकान दे, उसके बाद उस जमीन को एक्वायर करे। अगर ये ड्यूसिब के पास आती है तो माननीय मंत्री जी इसको देखें और उनको उन गरीब लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाये पहले उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो 14 तारीख तक का स्टे अगले महीने की 14 तारीख तक का स्टे कोर्ट ने दिया है उससे पहले अगर ये कार्रवाई होती है तो मेरे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं कि इतने साल से जहां वो बैठे थे, जहां पर उनके बच्चे पल रहे थे आज वो बड़े पीड़ित

हैं। तो मेरी आपसे पुन ये आग्रह रहेगा कि मेट्रो को आदेश दिया जाये कि पहले इन झुग्गियों को आप यहां से इन झुग्गीवासियों को पहले कोई रिहैबिलिटेशन काकार्य करे उसके बाद ही इनको हटाया जाये क्योंकि ये प्राईम रिस्पांसिबिलिटी मेट्रो की है। आपने मुझे इस बहुत ही गंभीर विषय पर, मेरे क्षेत्र के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः श्री मान रोहित मेहरोलिया जी।

श्री रोहित कुमारः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया है। बशीर भद्र जी का बहुत ही उम्दा शेर है किः-

'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में

तुम तरस तक नहीं खाते बस्तियां जलाने में'

भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है कैसे भी करके इलेक्शन जीतना है चाहे लोगों के घर जलाने पड़े, चाहे लोगों के घर तोड़ने पड़े। कई बार हमने देखा है और पूरे देश में अलग अलग उदाहरण हैं कि इलेक्शन जीतने के लिये लोग दंगे फसाद भी कराते हैं, उससे काम नहीं चलता तो लोगों को प्रलोभन भी देते हैं जैसे एमसीडी इलेक्शन के दौरान इन्होंने किया कि दिल्ली में तमाम झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से कहा गया, इनके बड़े बड़े नेताओं ने आकर कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी आकर कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गीवासियों ने सोचा कि शायद मोदी जी तो इस बार सच कह

रहे होंगे लेकिन इस बार भी उन लोगों को पुरानी जैसे 15 लाख वाले जुम्ले उनको हाथ लगे थे, इस बार भी उनको वही चीजें उनको देखनी पड़ी कि जगह जगह झुग्गियां तोड़ने के आदेश जारी कर दिये गये इलेक्शन हारते ही। तो ये जो हार की झुंझलाहट है, बौखलाहट है, वो साफ नजर आ रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके, दुरूपयोग करके दिल्लीवासियों से, गरीब जनता से कैसे बदला ले रही है। पचास पचास सालों से जो लोग एक जगह पर रह रहे हैं उन लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये सोचिये कि जब किसी को उजाड़ा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे भाई अभी नरेश यादव जी ने उदाहरण दिया मैहरोली का कि 12 दिसम्बर 2022 को वहां पर नोटिस भेज दिये गये कि 10 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दीजिये नहीं तो आपके घर तोड़ दिये जायेंगे। आप सोचिये दिल्ली के अंदर अभी हाड कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है माननीय अध्यक्ष जी, डेढ डिग्री, दो डिग्री टेंपरेचर चल रहा है ये लोग अपना बच्चों को लेकर, अपने सामान को लेकर कहां जायेंगे अभी पहलवान जी ने भी विस्तार से अपनी बातें रखी। ये गरीब लोगों का दर्द है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जिनके अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनकी पढ़ाई का क्या होगा। बगैर सोचेसमझे बस लोगों को उजाड़ना है इनको अपनी गंदी राजनीति को साध ने के लिये। माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले सत्र के अंदर मुझे मौका मिला था इसी विषय पर बोलने का और मैंने धन्यवाद ज्ञापित कराया था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिन्होंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी की थी इस विषय को लेके कि जहां झुग्गी वहां मकान की जो गरीब आदमी की जहां पर झुग्गी है वहीं पर उसको मकान बनाकर दिये जाने चाहियें आदेश

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया जिसके लिये मैंने उनको धन्यवाद भी दिया था और इस योजना के तहत दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने लगभग 47511 छोटे घर बनाने के लिये आदेश दिये थे। और बाद में केंद्र सरकार ने आदेश को पलटते हुए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम इनपे थोप दी गयी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी जहां पर उसको वहां पर उसको मकान दिया जाये इन्होंने वहां पर कह दिया कि उसको इस तरह नहीं देंगे। और आज खास तौर से जहां देखा जा रहा है कि जो डीडीए हर जगह जहां पर डीडीए की जमीन है, डीडीए का नाम अब तक लोग जानते थे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, लेकिन आज इसकी परिभाज़ा बदल रही है। अब ये बदलकर दिल्ली डराओ अथॉरिटी बन गयी है। दिल्लीवासियों में डर और आतंक भय का पर्याय बन गया है डीडीए। आज लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा और एक चीज और है अभी मैं एक टवीट देख रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि जिसमें हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक टवीट किया था और हिंदी में लिखा हुआ है 'जहां झुग्गी वहीं मकान' इन्होंने ये टवीट किया था 02.11.2022 को। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये इनकी करनी और कथनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? कि ये लोगों को लगातार उजाड़ने में लगे हुए हैं। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी एक ऐसी कालोनी से आता हूं दिल्ली के अंदर लगभग 45-46 ऐसी रिसेटलमेंट कालोनी त्रिलोकपुरी जैसी जहां का मैं नेतृत्व करता हूं, 1976 में कालोनी बसाई गयी थी हमारे परिवार ने वो दंश झेला है कि आनन फानन में वहां से उठाकर हमारे को नई दिल्ली के इलाके से उठाकर वहां भेज दिया गया था खुले आसमान

के नीचे। हमारे परिवार में आज तक चर्चा हमारे परिवार में हो रही है मां आज तक उसकी आंखें भर आती हैं वो अपनी परेशानियां बताते हुए कि किस प्रकार से। तो जब ये परिवार को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उसको विस्थापित किया जाता है तो सालों नहीं दशकों लग जाते हैं उनको संभलने में। बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना होता है, जो लोग कामधंधा अपने आसपास कहीं कोई कर रहे हैं, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है उनका रोजगार अगर आप उनको कहीं 40-50 किलोमीटर दूर कहीं फेंक देंगे तो कैसे उनका फिर से रोजगार सुनिश्चित हो पायेगा। इन चीजों को बगैर सोचे समझे लोगों को एक तुगलकी फरमान जारी करके लोगों को उजाड़ने का आदेश लगातार दिये जा रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरी तरीके से लोगों के साथ में बदले की कार्रवाई के तौर पर मैं इसको देखूंगा कि लोगों से बदला भारतीय जनता पार्टी ले रही है अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग करते हुए, एलजी साहब के इशारे पर तमाम तरह के इस तरह से लोगों को परेशान करने के षडयंत्र आए दिन रचे जा रहे हैं और हर विधान सभा में तकरीबन इन तरह की चीजें देखने को सामने आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहन आतिशी जी की विधान सभा के अंदर भी ये मुद्दा रहा, हमारे विधायक साथियों ने आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्ज़दों ने अब इनका घेराव भी किया था इसको लेकर। नवजीवन कैंप, नेहरू विहार और कालकाजी के अंदर गोसाई कालोनी मैहरोली के अंदर, कस्तूरबा नगर के अंदर। ये तमाम वो इलाके हैं कि जहां पर लोग आज डर के, भय के साये में जी रहे हैं कि कल क्या होगा। कल हमारे सर के ऊपर छत रहेगी या नहीं रहेगी माननीय अध्यक्ष जी। आज लोगों के दुख का ये आज ये सारा विषय है। तो आज मैं यही कहना

चाहूंगा केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधान मंत्री जी से कि लोगों के साथ में लोगों को ऐसे मत उजाड़िये, अपनी गंदी राजनीति को साधने के लिये लोगों पे ऐसे जुल्म करना बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं एक अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां यहां शेयर आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अब लोगों को पता लग गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, इनकी बातों पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं कि:

तेरे वायदों पर ऐतबार करूं तो कैसे करूं,
तेरे वादों पर ऐतबार करूं तो कैसे करूं,
तेरे हर वायदे को जुमलों में बदलते देखा है।
चाल चरित्र-चेहरे की बात करने वालों को
रोज नए सांचों में ढ़लते देखा है,
नहीं मंजूर अब नफरत की ये सियासत हमें,
नहीं मंजूर अब नफरत की ये सियासत हमें,
इस मंदिर-मस्जिद के झगड़े में देश को जलते देखा है,
इस मंदिर-मस्जिद के झगड़े में देश को जलते देखा है।

तो आज बहुत ही दुख का विषय है और मैं यही कहूंगा कि ये लोगों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिये, लोगों की तमाम बुनियादी सुविधाओं के ऊपर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार

काम कर रही है, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और लोगों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिये दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उसी प्रकार से केंद्र सरकार को भी ये सोचना चाहिये की गरीबों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना करें, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी आपने इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं अभी अपने पूर्व के साथियों को सुन रहा था, चाहे राजेश जी हों, चाहे नरेश जी हों, मेहरोलिया जी अपने देख व्यक्त कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की बेशर्मी का हद कर दिया, संवेदनशीलता इतनी मर गई है उनकी की इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं कि उन्हें ये भी नहीं याद आ रहा की इन्हीं जनता के पास उनको जाना है। कहीं पर शौचालय तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं पर 40-40 साल से झुग्गियाँ बसी हैं, उन झुग्गियों का तोड़ने का, उजाड़ने का काम कर रहे है। असल बात में ये जो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एलजी साहब कर रहे हैं। ये एमसीडी के इलैक्शन में हार का झूंझलाहट है उनका। मुझे याद है जब 2015 में सरकार बनी हमारी तो दिल्ली के हर झुग्गी-बस्तियों में शौचालय की बहुत कमी थी। मुझे शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया। मुझे याद है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 18 हजार शौचालय के यूनिट बनाए गए और उन्हीं शौचालयों की यूनिट के रूप में वजीरपुर में भी शौचालय बनाए गए। मॉडल टाउन विधान सभा में भी बनाए गए। मुझे याद है ऐसे-ऐसे जगह जहां पुलिस के बहुत बड़े-बड़े अफसर रहते हैं न्यू पुलिस

लाइन एनपीएल कालोनी है हमारे यहां। वहां पर मेन रोड पर झुग्गी थी और एक भी शौचालय नहीं था, राजेश जी जैसा बता रहे थे कि लोग मजबूरी में बाहर शौचालय/शौच जाते हैं। किसी को शौक नहीं है, शौचालय ही नहीं थे कहाँ जाते लोग। महिलाएं रोड के किनारे बैठती थीं, लोग गाड़ियाँ लेकर आते थे और उनको हम मजबूरी में फिर उठ जाना पड़ता था, गाड़ी चली जाती थी फिर बैठ जाते थे लोग। और इतनी गंदगी होती थी कि लोगों को पता चल जाता था कि आजाद पुर के आसपास कहीं पर आ गए हम लोग। लोग कहते थे बहुत गंदे लोग हैं लोग, ये लोग बहुत गंदे हैं टॉयलेट सड़क पर कर देते हैं। लोग गंदे नहीं थे अध्यक्ष जी, सरकारें गंदी थीं, जिनकी सोच गंदी थी उन लोगों को शौच जाने के लिये कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई थी। आदरणीय केजरीवाल जी ने इस बात को सोचा, हम लोगों ने जब इस बात को रखा कि पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होना चाहिये ताकि ओपन में शौच जाने के लिये किसी को मजबूर ना होना पड़े। ओपन में शौच को बंद करने के लिये 20 हजार से ज्यादा शौचालय ब्लॉक बनाए गए और आज एलजी साहब को एक अलग से भूत सवार हो गया है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के एक दूसरे अवतार पैदा हो गए हैं देश में। जिनको कभी-कभी दौरा पड़ता था, उनको जब भी दौरा पड़ जाता था उसको वो फरमान के रूप में जारी कर देते थे। अब एलजी साहब को दौरा जारी हो गया है कि हम एमसीडी के इलैक्शन में हार गए है। अब उसका बदला कैसे लेना है, बोले शौचालय तोड़ दो, बोले शौचालय तोड़कर क्या करोगे, बोले पार्क बनाएंगे, कमाल है। अध्यक्ष जी ये शौचालय जब बनाए गए थे तो डीडीए से बकायदा परमिशन ली गई थी। ये जगह डीडीए से अलॉट हुआ था, उसके लिये सरकार ने धन खर्च किया था, टैंडर हुआ

और टैंडर के बाद वो शानदार शौचालय बनाए गए और लोग उसमें जाते हैं। निशुल्क जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, साफ-सफाई की व्यवस्था होती है। महिलाओं को उनकी गरीमा के अनुरूप उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के लिये शौचालय बनाए गए की वो जाएं, उनको अपमान का सामना ना करना पड़े। लेकिन ना इनको बच्चों का, ना बच्चियों का, ना महिलाओं का, ना बुजुर्गो का किसी का ख्याल नहीं है। इसीलिये ये कर रहे हैं ऐसा। और इतने शौचालय बनाने से लोग बड़े खुश थे, झुग्गी-झोपड़ी के लोग। और नही ंतो और तमाम शौचालयों से अभी बहुत सारे रिकमंडेशन्स आए हैं कि और सारे शौचालय बनने चाहिये। जहां और शौचालय बनने की बात हो, जो शौचालय बने है बने बनाए तोड़ने की बात कर रहे हैं ये। मैं कहता हूं एलजी साहब ऐसे वोट नहीं देंगे आपको लोग। हम सौ मोहल्ला क्लीनिक बना रहे हैं, अरे आपको शौक है आपकी केंद्र की सरकार को, अपने भाजपा के आकाओं से कहिये, वो एक हजार बनाएं। जनता आपको चुन लेगी, अरे काम का कम्पीटिशन करना है तो स्वस्थ कम्पीटिशन करिये। हम पांच सौ स्कूल बना रहे हैं आप 5 हजार स्कूल बना दीजिए आपके पास पैसे बहुत हैं। हम 100 अस्पताल बनाने है, आप एक हजार अस्पताल बना दीजिए दिल्ली में आपको रोका कौन है। लेकिन कह रहे हैं हम बनाएंगे नहीं जो बने हैं उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो घबराइये नहीं, आएंगे 2024 में आपको भी तोड़ने का काम ये जनता के लोग करेंगें ये झुग्गी-झोपड़ी वालों से क्या दुश्मनी है भई आपकी। इन झुग्गी-झोपड़ी वालों के बच्चों के पढ़ाई के लिये, शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, उससे दुश्मनी है उसको फाइल को रोक देंगे आप। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के काउंटर चल रहे हैं, उस काउंटर को बंद करने का काम कर देंगे आप ताकि अस्पताल बंद हो जाए।

जल बोर्ड में उनके लिये पानी की व्यवस्था हो रही है पूरी दिल्ली में, यमुना को साफ करने का काम हो रहा है। आप कह रहे हो उसके लिये बजट रोक देंगे अधिकारियों से कहकर के। लोगों को स्वस्थ करने के लिये योगा के क्लासें चलाए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे थे। आप कह रहे हो नहीं लोगों को स्वस्थ नहीं रहने देंगे, योगा बंद करो। योगा बंद कर दिया आपने, क्या चल रहा है दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक पैदा हो गए, जब मन करता है तब जागते हैं सुबह-सुबह उनको भूत सवार हो जाता है।

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये आप।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आज शौचालय तोड़ दो जी, पार्क बना देंगे।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आरकियोलॉजिकल पार्क बना दो जी वहां पर, झुग्गी-झोपड़ी वालों को हटा दो।

माननीय अध्यक्षः कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः माननीय अध्यक्ष जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस करके जो एलजी साहब काम कर रहे है उसपर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिये। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाह रहा हूं इनके इस जुर्म पर की किस तरीके का जुर्म जनता के ऊपर एलजी साहब ढ़ा रहे है। लोग चुप नहीं होंगे। आज एक-एक दिल्ली का झुग्गी-झोपड़ी का लोग एक-एक गरीब लोग कह रहा है कि सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिये। ये भारतीय जनता पार्टी के सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिये।

जो काबिल नहीं उनसे कुर्सी छिन्ननी चाहिये, जो काबिल नहीं उनसे कुर्सी छिन्ननी चाहिये, कानून दे नहीं तो हम देंगे लेकिन जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिये, जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिये। अध्यक्ष जी इन लोगों को रोकने का काम ये सदन करे, आपके माध्यम से ये मेरा निवेदन है, इन गरीब लोगों पर जो मार पड़ रही है इनको रोकने का काम आप करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बी एस जून जी।

श्री बी एस जूनः धन्यवाद सर, सर जो झुग्गी कलस्टर्स हैं, इनको डिमोलिशन की तलवार हर वक्त लटकती रहती है। चाहे डीडीए की लैंड पर हो, चाहे फॉरेस्ट की लैंड पर हों, चाहे एएसआई की लैंड पर हों। कोर्टस का व्यूवज बड़ी क्लीयर है, की जब तक आप रिहैबिलिटेशन पैकेज लेकर नहीं आएंगे किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हर 15–20 दिन बाद एक नोटिस आ जाता है। पता नहीं क्यों नहीं ये लोग कोर्ट के स्टे ओर्डरस को भी cognizance क्यों नहीं ले रहे। क्लीयरली अभी उत्तराखंड के केस में शायद वो हल्दवानी या पीलीभीत का केस था जहां 60–65 साल से कॉलोनी बसी हुई थी। रेलवे वालों की रिक्वैस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने, रेलवे की रिक्वैस्ट पर उसको डिमोलिस करने का, पूरे गांव के गांव को, पूरी बस्ती को उजाड़ने का ओर्डर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जब तक आप इनको rehabilitate नहीं करेंगे किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो जितने भी ये नोटिसिज आ रहे हैं, अथोर्टिज को जो भी concerned उनको ये सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस या ओर्डरस या instructions का cognizance लेना चाहिये। आंख मिचकर

विंटर सीजन में एट लीस्ट ऐसे नोटिस इशू नहीं होने चाहिये। लेकिन आज कल ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की भी कोई नहीं सुनता है, रूलस–रैगूलेशन्स की बात कोई नहीं करता है। मेरी विधान सभा में सर मोस्टली जो कैंपस हैं वो फॉरैस्ट लैंड पर हैं। जैसे नरेश भाई ने बताया फॉरैस्ट वालों ने उनको फैंसिंग करके चारों तरफ से squeez कर दिया। एक उन्होंने, सिर्फ एक रास्ता छोड़ दिया। वहां पर दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर भी जाते थे, वहां पर डूसिब की गाड़ियाँ जाती, टॉयलेट क्लीन करने के लिये जाती थी। आज ना तो वहां टॉयलेट क्लीन करने के लिये डूसिब की गाड़ियाँ जा सकती हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पानी सप्लाई करने जा सकते हैं। क्योंकि और कोई आउटवे है ही नहीं और झुग्गियों के जो रास्ते हैं, वो दो–ढ़ाई–तीन फुट से ज्यादा नहीं होते। तो ये नहीं की एक पोर्सन से एंटर करके और rear portion में ये टैंकर या गाड़ियाँ पहुंच सकें। तो बहुत भारी दिक्कत है, गंदगी में वो लोग रह रहे है। एक नारकीय जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे है। मैंने फॉरैस्ट डिपार्टमेंट को कई चिट्ठी लिखी, की आप एटलिस्ट डूसिब की गाड़ियों को अंदर जाने दो एक गेट लगा दो, बेशक आप फैंसिंग करो। हम नहीं कहते इन्क्रोचमेंट बढ़नी चाहिए। आप फैंशिंग करके गेट लगा दो ताकि डूसिब की गाड़ी क्लीन करने के लिए जा सके और वाटर टैंकर जो उनको पानी सप्लाई करने के लिए जा सके। क्योंकि कोर्टस की डायरेक्शन्स हैं कि जब तक वे लोग वहां बैठे हुए हों उनको basic facilities, amenities देना सरकार का काम है। लेकिन शायद फोरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए भी आज तैयार नहीं है। डेली उनको एक नोटिस पकडा जाते हैं कि हम आपका झुग्ग्यों को डिमोलिश करेंगे। अब जब टायलेट्स में पानी नहीं पहुंचेगा, टायलेट्स क्लीन नहीं होंगे तो वहां पर stinking position

होगी या बदबू आ रही है। बीमारी आ रही है, वहां बीमारी फैल सकती है। मैने मंत्री जी को भी दो बार चिट्ठी लिखी की भई इनको कहा जाए फोरेस्ट डिपार्टमेंट को कि कम से कम इन जो essential services हैं इनको तो अलाउ करो। डूसिब की गाडियां जाने दो ताकि वो टायलेट्स क्लीन हो सके और वाटर के टैंकर जो है अंदर जा सके। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सर जितना भी जो फेंशिंग के अंदर का एरिया है उसमें ना तो कोई भी एक्टिविटी ये लोग करने नहीं देते। चाहे डीडीए हो, चाहे फोरेस्ट हो, चाहे एएसआई हो। जो गलियां बनी थी जो नालियां बनी थी वो पिछले पांच दस साल पहले बनी थी, उनको रिपेयर करने भी नही देते। अब वो लोग कहां जाए और दिल्ली में जितनी भी झुग्गीयां है तकरीबन हर constituency में झुग्गी हैं। इनको सिर्फ एक्सप्लोयेट करने के सिवाय आज तक किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। इनको उम्मीद जगी थी आम आदमी पार्टी से। टायलेट बनवाये। इनके लिए गलियां बनवाई, इनके लिए गलियां बनवाई। इनके लिए नालियां बनवाई। लेकिन अब दूसरी पार्टी जैसे एलजी साहब हैं या दूसरे जो भी लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई facilities, amenities देने की कोशिश ना की जाए और ना दी जाए ताकि ये लोग आम आदमी पार्टी से हटकर दोबारा से कहीं और शिफ्ट हो जाएं और ये इस चुनाव में जो पीछे जो एमसीडी का चुनाव आया था इसमें कोशिश की गई थी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ये लोग ना वहां कोई मैडिकल फैसिलिटी है, ना कोई सेनेटेशन की फैसिलिटी है, ना पानी की फैसिलिटी है। हर लिहाज से ये deprived हैं और ऑथोरिटीज इनके बारे में कुछ नहीं सोच नहीं है। जो फैसिलिटीज हैं उनको undone करने की कोशिश हो रही है कि अगर वो पोर्टेबल मोबाइल टायलेट्स करें है तो उनमें पानी नहीं

है वो stink कर रहे हैं आज। कोई भी महामारी वहां फैल सकती है। तो हमारी और जितने हमारे एमएलऐज है जो इन्होंने रेज किया मैं भी उससे सहमत हूं और मेरा मिनिस्टर कन्सर्ड जो हमारे बैठे फोरेस्ट डिपार्टमेंट के उनसे हाथ जोड़ कर विनती है कि इनकी एक मिटिंग बुलाएं फोरेस्ट वालों की और एक दुख दर्द से जिसमें आज ये लोग जी रहे हैं उनसे इनको निजात दिलवाये सर। ये बहुत जरूरी है humanitarian ground पर क्योंकि बीजेपी वाले बिल्कुल ही नहीं चाहते कि झुग्गियों में कोई विकास काम हो। विकास कार्य कोई हो। उनका एक ही प्रपज है किसी तरीके से इनको आम आदमी पार्टी को दूर किया जाए। पहले कांग्रेस इनको एक्सप्लोऐट करती रही, अब बीजेपी वाले इनको जो है टार्चर कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये ही अनुरोध है कि इनकी कन्डीशंस पर इनकी plight प्लीज कुछ ना कुछ सोचा जाए। ताकि इनकी जो सर दयनीय स्थिति है उस में कुछ सुधार आए और इनका जो एरिया है वो रहने के लायक बन सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी नमस्कार। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज पूरी दिल्ली की स्थिति हमारे सारे विधायक साथियों ने विस्तार से बताई है और मेरा जो क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में कम से कम डेढ लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा व्यवसायिक जो केन्द्र है मोती नगर विधान सभा में है। वहां पर लक्कड़ मार्किट है। फर्नीचर मार्किट है, मार्बल मार्किट है, पीवीसी मार्किट है और कीर्ति नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया है, डीएलएफ इन्डस्ट्रीयल एरिया है, रामा रोड है, कार शोरूम्स हैं। सारे बैकेंट की सबसे बड़ी मार्किट है। जिसमें

हजारो लाखों एम्पलाईज काम करते हैं। उनका ठिकाना वही है झुग्गियों में रहने का और वो झुग्गी निवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए हमारी सरकार आई तो उन्होंने शौचालय बनाए। उनके लिए व्यवस्थाएं की। आज जिस तरह से आर्डर ईशू किये जा रहे हैं झुग्गियों को तोडने का और ये झुग्गियों को तोडने के नोटिस हमारे क्षेत्र में भी चिपकाए जा रहे हैं। 5/35 कीर्ति नगर में चिपकाया गया। 8/35 में भी चिपकाया गया और 8/35 में कुछ झग्गियां तोडी भी गई। तो आज ये डर का माहौल हर झुग्गी वासी के अंदर है। आज उनके लिए लगता है कि इन सर्दियों में जिस तरह से शौचालय तौडे गए। वजीरपुर के अंदर और मेरे यहां पर ग्यारह सीटों का निर्माण हुआ शौचालयों का। तो आप उससे पहले आप समझे कि उससे पहले क्या स्थिति होती होगी एक झुग्गी वासियों की। वो जो भी अपना टॉयलेट करते होंगे, रेलवे लाईन पर सड़कों पर। आज कहीं ना कहीं उन दशा को दिशा को सुधारा गया दिल्ली सरकार के माध्यम से। उनके लिए स्कूल बनाए गए। उनके बढ़िया सुविधाएं दी गई। ताकि वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जब भी इलैक्शन्स आते हैं। चौदह में इलैक्शन हुए तब बड़े-बड़े होर्टिंग लगे। जहां झुग्गी वहीं मकान। उसके बाद 15 में, 19 में 20 में और अब ये रिसेंटली 22 में। प्रधान मंत्री जी की बड़ी-बड़ी होर्टिंग लगाई गई और कहा गया कि जहां झुग्गी वही मकान दिये जाएंगे। लेकिन एमसीडी जाने का इतना इनको दर्द हो रहा है कि अपने वायदे इन्होंने हर वायदे को इन्होंने चुनावी वादा किया और हर वायदे को इन्होंने झुठवाया। जो भी आज तक कहा है आखिर चुनावी वादा बनकर रह गया। तो आज जो स्थिति पूरे देश में और पूरी दिल्ली में है हमारी विधान सभा में है। जो ये डर का माहौल है इस डर के माहौल के

ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। जो जनता अभी फिर भी एक आराम की सुविधा में रह रही है उस सुविधा को बनाये रखने के लिए जो भी हमें उसके लिए कुछ करना पड़े करना चाहिए। तो ये हमारा मानवीय कर्तव्य भी है और वैसे भी हमें जो भी जीवन में एक बेसिक समस्या है वो कम करने का जो हमारा धयेय है वो करना चाहिए। तो इसके लिए हमें जहां भी जाना पड़े हमें सब मिलकर जाना चाहिए। शुक्रिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः आतिशी जी।

श्रीमती आतिशीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय अभी–अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ। चुनाव का नतीजा आए चार हफ्ते पांच हफ्ते हुए। जब चुनावी campaign चल रहा था। हर पार्टी अपना प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही थी। कांग्रेस अपना प्रचार कर रही थी। आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही थी। हर पार्टी ने कुछ वादे किये कि हम अगर हम चुनाव जीतते हैं अगर आप हमें वोट देते हो तो हम आपके लिए स्कूल बनायेंगे, अस्पताल बनायेंगे, मकान बनायेंगे, दिल्ली को साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान एमसीडी चुनाव के campaign में दिल्ली में हर हिस्से में जाकर जो सबसे बड़ा वादा किया और हमारे बहुत सारे विधायक साथी यहां पर बैठे हैं उनकी इलाकों में आ आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक सबसे बड़ा वादा किया कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी ही विधान सभा में कुछ in-situ rehabilitation के फ्लैट्स बने। पूरी दिल्ली भर से बसें भरकर वहां पर लोगों को लाया गया। दिखाया गया कि ऐसे मकान भारतीय जनता पार्टी झुग्गी में रहने वालों को देगी

और जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देगी। ये नवम्बर की बात होगी जब एमसीडी के चुनाव का प्रचार चल रहा था। चार दिसम्बर को वोट पड़े। सात दिसम्बर को नतीजे आये। जैसे ही एमसीडी चुनाव के नतीजे आये। आने वाले कुछ ही हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी के वादे का झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया। उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं दिल्ली में अनेकों जगह मकान देना तो बहुत दूर की बात है झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगने लग गया दिसम्बर के महीने से लगने लग गया। मेरी अपनी विधान सभा क्षेत्र में जहां पर दिल्ली भर से लोगों को लेकर आये कि तुम्हें ऐसे फ्लैट देंगे उन फ्लैट्स से पांच सौ मीटर की दूरी पर जो झुग्गियां हैं और बहुत बड़ी-बड़ी झुग्गियां हैं। नवजीवन कैम्प और नेहरू कैम्प के नाम से जहां पर पचास हजार से ज्यादा लोग रहते हैं उन फ्लैटों से पांच सौ मीटर दूर जो झुग्गियां हैं, उनके सामने नोटिस लगा दिया गया कि तुम्हें नरेला में फैंक देंगे और तुम्हारी झुग्गी पर बुलडोजर चला देंगे। एक महीना नहीं हुआ चुनाव का नतीजा आये। जब वहां के स्थानीय लोगों ने यह मुद्दा उठाया जब हमने ये मुद्दा उठाया तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूडी जी आये। एक महा पंचायत करके उन्होंने वहां की जनता को सरासर झूठ बोला और बोला कि नहीं-नहीं हमने नहीं लगाया। नोटिस गलती से लग गया होगा। किसी अफसर ने लगा दिया होगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं है सरकार का। उनके भी झूठ का पर्दाफाश हो गया जब उनकी ही डीडीए ने दो दिन बाद फिर से नया नोटिस लगा दिया कि इन झुग्गियों को नरेला भेजा जा रहा है और यहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ दिन बाद हमने देखना शुरू किया मैने और विधायकों से बात करी तब पता चला कि ऐसा ही नोटिस महरौली

में लग गया है और महरौली में जो नोटिस लगा उसमें तो साफ-साफ लिख दिया कि दस दिन के अंदर इन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। फिर ये खबर आई तुगलकाबाद की हमारे माननीय विधायक सहीराम जी भी बैठे हैं तुगलकाबाद गांव पर भी केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने नोटिस लगा दिया कि दस दिन में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हमारे नेता विपक्ष यहां पर मौजूद नहीं है, मैं उनको भी दिखाती कि उनकी अपनी विधान सभा क्षेत्र में भी उनकी अपनी ही पार्टी द्वारा शासित डीडीए ने कल सुबह सुभाष कैम्प पर नोटिस लगाया है कि वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि गलती से नोटिस लग गया है लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है कि किसी तरह से पूरी दिल्ली की झुग्गियों को साफ कर दें। क्यूं साफ कर दें? क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी वाले रहते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं।

यही भारतीय जनता पार्टी थी जो एक महीने पहले वादा कर रही थी कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके अलग-अलग विभाग दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में नोटिस लगा रहे हैं कि इन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा शासित डीडीए को एक बात बताना चाहूंगी कि वो चाहे दिल्ली में कितने भी नोटिस लगाते रहें लेकिन जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के विधायक हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक भी सिपाही जब तक रहेगा हम दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं

चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो दिल्ली के गरीबों को दबा सकती है, झुग्गियों पर बुलडोजर चला सकती है तो मैं उनको चेतावनी देना चाहती हूं कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिल्ली विधानसभा से साफ कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने उन्हें एमसीडी से निकाल कर बाहर कर दिया है वो दिल्ली के गरीबों पर इस तरह से अत्याचार करते रहेंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में दिल्ली वाले उन्हें लोकसभा से भी साफ कर देंगे क्योंकि वो गरीबों पर इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकते हैं और जब तक आम आदमी पार्टी है हम दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी उत्तर दें उससे पहले राजेश जी जो आपने कमेटी को रेफर करने की बात की थी ये विभिन्न विधायकों से क्योंकि अलग-अलग विधायकों के अलग-अलग क्षेत्र हैं वो अलग क्षेत्रों से विधायकों से लिखकर मेरे पास आ जाएं फिर मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री राजेश गुप्ताः जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गोपाल राय (माननीय पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दू पर चर्चा कर रहा है। क्योंकि जब से मनुष्य धरती पर पैदा हुआ चाहे वो दुनियां के किसी कोने में हो सभी धर्मो से सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। दिल्ली के अंदर बड़ी-बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाएं भी हैं लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली के उन गगनचुंबी अट्टालिकाओं के

लोगों की जिंदगी को संचालित करने वाले लोग आजादी के 75 साल बाद भी झुग्गियों में एक अमानवीय जीवन जीने के लिए आज भी मजबूर हैं। दिल्ली के अंदर झुग्गियों में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग इलाकों में जो लोग रहते हैं वो खुशी से नहीं रहते हैं। अध्यक्ष जी, 75 साल बाद जब ये भारत हमारा देश आजादी के 75 वें वर्षगांठ मना रहा है जो भी विभाग जो भी अधिकारी जो भी पार्टी जो भी नेता इस बात को सोच रहे हैं कि दिल्ली के अंदर से झुग्गियों का सफाया कर देंगे वो झुग्गियां नहीं हैं उसमें इंसान रहते हैं जिंदा इंसान। उनको इस बात को सोचना बहुत ही जरूरी है कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी हम भारत के बेटे-बेटियों को इस लायक भी क्यों नहीं बना पाए की उनको झुग्गी में रहने की जरूरत न पड़े। दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2014 से लेकरके लगातार ये बात आती रही की दिल्ली के अंदर झुग्गियां बढ़ रही हैं। जब हमारी सरकार बनी 2015 में हमने एक निर्णय लिया की नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए लेकिन जो झुग्गियां पहले से हैं उन झुग्गियों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए पुनर्वास की व्यवस्था हुए बगैर उनको हटाया नहीं जा सकता लेकिन सरकार दिल्ली की सरकार दिल्ली के दो करोड़ लोगों से चुनी हुई सरकार जब दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर को देश के संविधान से फर्क नहीं पड़ता। जब दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर, लेफ्टीनेंट गवर्नर नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। मैं तो कई बार भ्रम में पड़ जाता हूं कि लेफ्टीनेंट गवर्नर भाजपा के प्रवक्ता हैं या भाजपा लेफ्टीनेंट गवर्नर की प्रवक्ता है समझ में नहीं आता है। जो काम भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जाकर के नहीं कर पाती है वो लेफ्टीनेंट गवर्नर के पीछे छुपकर के वार करती है। अध्यक्ष महोदय जिसकी

हमारे सदन के सदस्यों ने बार–बार चर्चा की कि यही दिल्ली है देश के माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव से पहले आते हैं, गुजरात का चुनाव छोड़कर आते हैं और कालका जी में जाकर के तामझाम के साथ वीडियो चलाया जाता है लाइव किया जाता है की जहां झुग्गी वहां मकान देखो केजरीवाल तो नहीं दे पाया देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है अगर एमसीडी चुनाव में फूल का बटन दबाओगे तो चुनाव के बाद जहां झुग्गी वहीं मकान पाओगे। दिल्ली के लोग कोई पहली बार तो नहीं आए भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों ने देखी है। आठ साल से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर डीडीए के कोई पहली बार नोटिस नहीं आ रही है। जब भी मन करता है मुझे नहीं लगता की कौन फटाफट टाइप करता है और नोटिस जाकर के चस्पा कर देता है। दिल्ली के लोगों ने उन सारे प्रचार के बावजूद ये फैसला किया की अगर दिल्ली के अंदर झुग्गी में रहने वालों की जिंदगी की उनके बच्चों की उनके बुजुर्गों की उनके लिए टायलेट की उनके लिए साफ पानी का इंतजाम बिजली–पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है और आगे भी अगर हमारी जिंदगी पर संकट आएगा तो उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा होगा तो अरविंद केजरीवाल खड़ा होगा आम आदमी पार्टी खड़ी होगी इसलिए लोगों ने समर्थन किया लेकिन चुनाव के बाद ये इतना बड़ा करिश्मा की आप पूरी दिल्ली को रोंदने की तैयारी कर रहे हैं। संवैधानिक तौर पर एलजी साहब अपने आपको शासक मानते होंगे। अभी ये मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्होंने कहा कि हम संविधान एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, शासक हूं। अध्यक्ष महोदय जहां

पर सत्ता में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले शासक पैदा होते हैं इतिहास गवाह है ऐसे बड़े-बड़े शासकों को नेस्तनाबूत करने वाली जनता की ताकत फिर पैदा होती है और उसको नेस्तनाबूत करती है। जनता की ताकत से आजादी मिली भारत को, जनता की ताकत से भारत का संविधान पैदा हुआ, जनता की ताकत से सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिली है, जनता की ताकत से दिल्ली की विधानसभा है और अगर जनता की ताकत को नजरअंदाज करके शासक बनने का कोई सपना देख रहा है तो उस सपने को चकनाचूर करने की ताकत भी जनता के अंदर है। इतिहास के पन्ने को मिटाया नहीं जा सकता इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं केवल इतना कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार का बहुत ही स्पष्ट मत है। अभी हमारे माननीय विधायक जून साहब ने कहा फारेस्ट ने कई जगहों पर नोटिसें जारी की, कई जगह पर नोटिसें जारी की हमने मीटिंग करके कई जगह रद्द भी करवाए। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया है उनको meeting करके अधिकारियों से भी चूंकि हर अधिकारी पर दबाव है, हर अधिकारी पर दबाव है इसलिए अध्यक्ष महोदय सरकार का बहुत ही स्पष्ट निर्णय है कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है तब तक जो है कोई भी डिमोलिशन नहीं हो सकता। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले डायरेक्शन भी जारी किया है की इस तरह से कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जा सकती है। मैं केवल दो ही बात कहना चाहता हूं संवैधानिक तौर पर जो सरकार के पास अधिकार है संवैधानिक तरह से हम जनता के साथ खड़े होंगे और जहां कानून और सख्ती का दायरा शासकों के अहंकार में छोटे पड़ने लगेंगे ये आम आदमी की बटालियन है पूरी ताकत से सड़क पर उनके साथ लड़कर के जाड़े का मौसम हो या गर्मी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास बुलडोजर

है चलाने के लिए तो आम आदमी पार्टी के पास सीना है उसके सामने खड़ा होने के लिए। इस मुहिम को हम रोकेंगे सरकारी तौर पर भी रोकेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पूरी सरकार सड़क पर भी उतरकर इसके लिए लड़ेगी। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है हम जनता के साथ खड़े हैं वो भारत के बेटे-बेटियां हैं और भारत का संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है इसलिए जिंदगी सर्वोपरि है, जिंदगी बचाना सर्वोपरि है, जिंदगी को बसाना सर्वोपरि है, जिंदगी को चलाना सर्वोपरि है, जिंदगी से बड़ा कोई कानून और कोई नियम नहीं बन जाएगा इसलिए अध्यक्ष महोदय हम सबको मिलकर के इस पर प्रयास करने की जरूरत है। माननीय लेफ्टीनेंट गवर्नर से भी कहना चाहता हूं, डीडीए से भी कहना चाहता हूं और खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली सरकार की तरफ से जो वादा किया था हर वादे को जुमला मत बना दीजिए इंसान है इंसान को जिंदा रखने के लिए सर के ऊपर से पानी जब गुजरेगा तो उससे लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से झुग्गी के लोगों के साथ है और अंतिम समय तक हम उनके लिए लड़ेंगे शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सभी शाम को जैसा मैंने पहले कहा था कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।